

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-18, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : 888009@cgmail.com

विषय— राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 10/08/2023 को संपन्न 480वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023 को डॉ. बी.पी. सोनवरे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया—

1. डॉ. शैलेष कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 2. श्री एन.के. चन्दाकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 3. श्री किसान सिंह छुए, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 4. डॉ. मन्मोज कुमार चौपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 5. श्री कल्पदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
- समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया—

एजेण्डा आयटम क्रमांक-1: 478वीं एवं 479वीं बैठक क्रमशः दिनांक 27/07/2023 एवं 28/07/2023 को कार्यवाही विवरण के अनुसूचन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 478वीं एवं 479वीं बैठक क्रमशः दिनांक 27/07/2023 एवं 28/07/2023 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेण्डा आयटम क्रमांक-2: ग्रीन/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परिवर्तनकारी संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मैसर्स दुलना साईन स्टोन क्वारी (प्री- बीमती जनिता जैन्), घाम-दुलना, ताहसील-अमनपुर, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2487)

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीपी/ एम्आईएल/ 429/88/2023, दिनांक 01/08/2023 द्वारा टीओआर आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संघलित चूना पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान घाम-दुलना, ताहसील-अमनपुर, जिला-रायपुर

निम्न खसरा क्रमांक 432/3, 433/2, 673 एवं 674, कुल क्षेत्रफल-2.082 हेक्टर में है। खदान की अधिकतम उत्खनन क्षमता-28,500 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस्.ई.ए.सी., जलसिंचन के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु की चुनांगु चौधरी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा वस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

- पूर्व में चुना पाथर खदान खसरा क्रमांक 432/3, 433/2, 673 एवं 674, कुल क्षेत्रफल-2.082 हेक्टर, क्षमता-10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सम्पादा निर्धारण प्रधिकरण, जिला-रायपुर द्वारा दिनांक 18/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 18/12/2022 तक की अवधि हेतु वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"3A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 18/12/2023 तक वैध होगी।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल भवन से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का चलन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- निर्धारित अर्हानुसार कुशलरोप्य नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-रायपुर, को ज्ञापन क्रमांक 2321/खनिज/घु.प./न.क-एसी13/2023 रायपुर, दिनांक 04/08/2023 द्वारा विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2018-19	4,000
2019-20	10,000
2020-21	10,000
2021-22	10,000
2022-23	10,000

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2023 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन एवं कचरा स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत दुलना का दिनांक 12/08/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - गौडिचोईक ऑफ कचारी प्लान एलांग विथ कचारी मलोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.) संचालनालय भीमिडी तथा खनिज, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर के पृ. ज्ञापन क्र. 2374/खनि 02/मा.प्र.अनुमोदन/प.क्र.04/2019(3) नवा रायपुर, दिनांक 05/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1060/कोष/उ.प./चुन.पत्र/2023-24 रायपुर, दिनांक 28/05/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, कुलफल 8.887 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1060/कोष/उ.प./चुन.पत्र/2023-24 रायपुर, दिनांक 28/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरुपट, कुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। 200 मीटर के भीतर ग्राम दुलना की आबादी स्थित है।
6. लीज का विवरण - लीज श्रीमती अनिता जैन के नाम पर है। लीज डीक 10 वर्षों अवधि दिनांक 18/12/2022 से 18/12/2032 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परिपोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज अवधि 18/12/2002 से 18/12/2032 तक है। समिति का मत है कि दिनांक 18/12/2002 से दिनांक 18/12/2022 तक की अवधि का लीज डीक की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. चू-स्वामित्व - चूनि श्री शंयांश जैन के नाम पर है। उत्खनन हेतु चू-स्वामी का सहमती पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-दुलना 29 मीटर, स्कूल ग्राम-दुलना 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राजमार्ग 5 कि.मी. दूर है। महानदी 408 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैववैविधता संवेदनशील क्षेत्र - परिपोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिंटकली पॉइन्टुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होगा प्रतिवेदित किया है।

12. खनन संयंत्र एवं खनन का विवरण – जियो-लॉजिकल रिजर्व 8,83,825 टन एवं बाई-नेचल रिजर्व 1,50,000 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,100 वर्गमीटर है। अल्पन कार्बट सोनी मैग्नीशियम विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में ऊपर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिद्धांत किया जाता है। वर्षाकर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	30,000
द्वितीय	30,000
तृतीय	30,000
चतुर्थ	30,000
पंचम	30,000

समिति द्वारा नोट किया गया कि प्रस्तुत मॉडिफाईड क्वारी प्लान अनुसार वर्षाकर प्रस्तावित उत्खनन क्षमता ऑनलाईन के माध्यम से किये गये आरेखन में उत्खनन क्षमता 28,500 टन प्रतिवर्ष से अधिक है। समिति का मत है कि ऑनलाईन के माध्यम से किये गये आरेखन में उत्खनन क्षमता अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरेवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत सेंट्रल वायुमंडल बोर्ड अधीनस्थिता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में तारों और 7.5 मीटर की पट्टी में 400 गण वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 5,100 वर्गमीटर है, जिसमें से 2,830 वर्गमीटर क्षेत्र 10 मीटर की गहराई तक 670 वर्गमीटर क्षेत्र 13 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उत्तरांश है। कर्मालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 114/खनिज/सु.प.व.व./अनु.नो.प्ला./2022 रायपुर, दिनांक 19/01/2023 द्वारा जारी पत्र अनुसार परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध खनिज विभाग द्वारा अर्थात् उत्खनन किये जाने हेतु अर्थात्पत्र राशि रुपये 1,05,000/- लगाया गया था, जिसको परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 13/01/2023 द्वारा अर्थात्पत्र राशि रुपये 1,05,000/- खनिज विभाग में जमा किया जाकर रसीद की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अर्थात् उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु जमानत पर्यावरण संरक्षण

Handwritten signature

मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि उल्लिखित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्भरण प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पक्षियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीम कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 13(a) के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र को अंदर 7.5 मीटर चौड़े सुरक्षा क्षेत्र में वृक्षरोपण किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुत मीटिंगाईड क्वीरी प्लान अनुसार खदान से घास दुलना की दूरी 20 मीटर का उल्लेख है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा से घास दुलना की न्यूनतम दूरी 50 मीटर होनी आवश्यक है। अतः घास दुलना से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी तक गैर माइनिंग क्षेत्र छोड़ते हुए रिजर्व की गणना कर संशोधित क्वीरी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्बन्धि से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. घास दुलना से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी तक गैर माइनिंग क्षेत्र छोड़ते हुए रिजर्व की गणना कर एवं ऑनलाईन के माध्यम से किचें नर्स आवेदन में उल्लेखन क्षमता अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित क्वीरी प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. उल्लिखित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्भरण प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाए।
3. 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पक्षियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाए।
4. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. दिनांक 01/04/2020 से किए गए उल्लेखन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
6. दिनांक 18/12/2002 से दिनांक 18/12/2022 तक की अवधि का लीज क्षेत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
7. लीज क्षेत्र से निकलने वाला क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग, कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से अनुरोधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

1. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अधिक उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक को विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

2. मेसर्स एन.एस. इस्पात (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (युनिट-2), उरला औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम-सरोरा, तहसील-धरसीवा, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2901)

ऑनलाईन आवेदन - एप्लोअल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनवी1/ 432030/2023, दिनांक 02/06/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा उरला औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम-सरोरा, तहसील-धरसीवा, जिला-रायपुर, प्लॉट नं. 101/29, खसरा क्रमांक 411/3, कुल क्षेत्रफल-0.406 हेक्टेयर में रेगुलार्इजेशन ऑफ रि-रोलड प्रोडक्ट्स (ब्लिन्ड, वैनल्स, पिल्लर्स एवं गिडर्स फॉर स्ट्रक्चर्स आयरन एण्ड स्टील) क्षमता-30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनिर्माण 3 करोड़ रुपये होगा।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईसी, छत्तीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 02/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 490वीं बैठक दिनांक 16/06/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नुकेंडा पाण्डेय, डायरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. जल एवं वायु सम्बन्धि -

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि-रोलड प्रोडक्ट्स (ब्लिन्ड, वैनल्स, पिल्लर्स एवं गिडर्स फॉर स्ट्रक्चर्स आयरन एण्ड स्टील) क्षमता - 30,000 मिट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु संवाहन सम्बन्धि दिनांक 18/01/2021 को जारी की गई, जिसकी सम्बन्धि नवीनीकरण किया दिनांक 31/10/2024 तक है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्बन्धि शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्बन्धि शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **सू-स्वामित्व** – सू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज (अप-विषय) प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार भूमि मेसर्स एन.एस. इस्पात (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (युनिट-2) के नाम पर है।
3. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –
 - समीपस्थ आबादी घाम-सरोवर 540 मीटर निकटतम रेल्वे स्टेशन इन्ड्यूआर, एन. कॉलोनी 3.8 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानक्षेत्र, नागा, रायपुर 18 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 कि.मी. एवं खासम नदी 8 कि.मी. दूर स्थित है।
 - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्तर्राज्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
4. **क्षेत्र परिचा स्टेटमेंट** –

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Rolling Mill Area	1,040.00	25.68
2.	Raw Material Area	445.00	11.01
3.	Finished Products Area	410.00	10.12
4.	Parking Area	120.00	2.96
5.	Office	55.00	1.36
6.	Green Belt Area	1,620.00	40.00
7.	Road Area	250.00	6.17
8.	Open Area	109.00	2.70
Total		4,050.00	100

5. **सू-मटेरियल सप्ला** –

S.No	Raw Material	Quantity (MTPA)	Source	Mode of Transport
1.	Billets/ Ingots	31,500	Open Market	Road

6. **प्रस्तावित कार्यकलाप का विवरण निम्नानुसार है-**

S. No.	Particular	Proposed
1.	Unit	Regularization of existing Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products – 30,000 TPA

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोल मैसीकायर आधारित रि-रॉलिंग फर्नेस रोलिंग मिल स्थापित है। पर्यावरणीय इस्टिमेट परिसर नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।
8. **कोल अपशिष्ट उपचयन व्यवस्था** – रोलिंग मिल से मिल स्केल-800 टन प्रतिवर्ष एवं एचड कॉटिंग-700 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्केल एवं एचड कॉटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाना बताया गया है।
9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्क्रैप** - परियोजना हेतु वन टाईम वॉटर डिमांड 8 घनमीटर प्रतिदिन है। परियोजना हेतु डेक वॉटर कुल 5 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, धोखु उपयोग हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट एवं कल्ट रीजन हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति मू-जल से की जाती है। मू-जल की उपयोगिता हेतु सेंट्रल प्राइमरी वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** - औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरोक्त जमित दूषित जल को उठा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। परंतु दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। सूच्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।

- **मू-जल उपयोग प्रबंधन** - परियोजना स्थल सेंट्रल प्राइमरी वाटर बोर्ड की अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार-

(अ) कृहर एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःउत्पन्न एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) प्राइमरी वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक क्या रेनवाटर हावैरिंटिंग /ऑटिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर मू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल प्राइमरी वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हावैरिंटिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हावैरिंटिंग व्यवस्था** - रेन वॉटर हावैरिंटिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्क्रैप** - परियोजना हेतु कुल 3 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होती है। विद्युत की आपूर्ति एनटीएसएड राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। समिति का मत है कि वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट ऑफिशियलेशन एवं विन्पी की लीडाई के संबंध में जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** - हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.182 हेक्टर (40 अक्षेत्र) क्षेत्र में 405 नम पौधों का वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फीसिंग, खाद एवं सिंचाई तक रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का कर्मचार घटक-कार एवं समय-कार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 मार्च 2023 से 31 मई 2023 के मध्य किया गया है।**

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall

apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3280(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैंडर्ड टर्म ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरींग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अन्धर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन-फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई:-

- i. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.
- ii. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.
- iii. Project proponent shall submit air pollution control arrangement alongwith stack height details and pollution emission level calculation.
- iv. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- v. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year.
- vi. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.
- vii. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier along with its capacity use in reheating furnace.
- viii. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.
- ix. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.
- x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xii. Project proponent shall submit the Central Ground Water Authority NOC for uses of water.
- xiii. Project proponent shall submit data of the quantity of ash generated from coal burning and the drainage system.
- xiv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- xv. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

- xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xviii. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xix. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.
- xx. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

सूच्य सार्वीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिकरण (एस.ई.आई.ए.) अस्तीसगद को तदानुस्तर सुचित किया जाए।

3. केसर शिव रिपल इस्पात प्राईवेट लिमिटेड (युनिट-2), ग्राम-चरीदा, तहसील-चरसीवा, जिला-रायपुर (सकिकालय का नस्ती क्रमांक 2902)

अंनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 432073/2023, दिनांक 03/08/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-चरीदा, तहसील-चरसीवा, जिला-रायपुर, खसरा क्रमांक 422/1, 423/2, 424, 425 एवं 426/1, कुल क्षेत्रफल-2.42 हेक्टेयर, रेगुलरईजेशन अंनक रि-रोल्ल स्टील प्रोडक्टरा क्षमता-30,000 मिट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग 2.88 करोड़ रुपये होगा।

तदानुस्तर परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. अस्तीसगद को स्थापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 430वीं बैठक दिनांक 10/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कोशिक पटेल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निश्चति पाई गई-

1. जल एवं वायु सम्पति -

- क्षेत्रीय कार्यालय, अस्तीसगद पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि-रोल्ल प्रोडक्टरा (यू इम्प्लेशन अर्नेस) क्षमता - 30,000 मिट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु संकलन सम्पति दिनांक 10/08/2023 को जारी की गई, जिसकी कैपता संवाहन प्रारंभ नस्ती के प्रथम दिनांक से 12 माह की अवधि

(Handwritten signature)

रक है। समिति का मत है कि उद्योग संचालन प्रारंभ की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. भू-स्वामित्व - प्रस्तुत भूमि संबंधी दस्तावेज अनुसार भूमि श्री अरुण पटेल के नाम पर है। समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा जारी सम्मति नवीनीकरण में खसरा क्रमांक 422/1, 423/2, 424, 425 एवं 426/1 का उल्लेख है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में खसरा क्रमांक 422/1, 423/2, 424, 425 एवं 426/1 का कुल क्षेत्रफल 2.42 हेक्टेयर बताया गया है, जबकि क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जारी सम्मति नवीनीकरण में खसरा क्रमांक 422/1, 423/2, 424, 425 एवं 426/1 का कुल क्षेत्रफल 1.155 हेक्टेयर का उल्लेख है। समिति द्वारा यह भी पाया गया कि जल खासों के अनुसार प्रस्तुत भूमि संबंधी दस्तावेजों में उल्लेखित क्षेत्रफल में गिनता है। समिति का मत है कि उपरोक्त विसंगतियों के संभव में भूमि दस्तावेजों की पुष्टि बाबत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल एवं परियोजना प्रस्तावक से स्पष्ट जानकारी मांगी जाना आवश्यक है। साथ ही यह भी मत है कि उल्लेखित क्षेत्रफल एवं खासों में गिनता होने के कारण प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में विचार किया जाना संभव नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक को आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुमति दी गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2008 (यथा संशोधित) के तहत चलान करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुमति दी गई। साथ ही उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल एवं परियोजना प्रस्तावक को भूमि दस्तावेजों की पुष्टि बाबत पत्र लेख किये जाने की अनुमति दी गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रियण (एस.ई.आई.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सुचित किया जाए।

4. मेसर्स विनायक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, डाम-पाली, ताहसील व जिला-रायगढ़ (सचिवालय का नशी क्रमांक 1748)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजित नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनबी/ 65904 / 2021, दिनांक 22/07/2021 द्वारा ही.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजित नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनबी/ 432136 / 2023, दिनांक 05/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाइनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा डाम-पाली, ताहसील व जिला-रायगढ़ जिला खसरा क्रमांक 28/2, 29/1, 29/3, 29/4 एवं 29/5, कुल

संयोजक - 553 हेक्टर (13.87 एकड़) में बीजाच्छाई प्लांट (स्पंज आयरन) क्षमता - 62,700 टन प्रतिवर्ष (35 टन प्रतिदिन गुणा 2 नम), डब्ल्यूएचआरबी आधारित पीपर प्लांट क्षमता - 8 मेगावॉट (13.8 टन प्रतिघंटा गुणा 2 नम) एवं एकबीसी आधारित पीपर प्लांट क्षमता - 8 मेगावॉट (36 टन प्रतिघंटा गुणा 1 नम) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना की कुल लागत 110 करोड़ होगी।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. धरतीसमूह को आपन दिनांक 11/03/2022 द्वारा प्रकरण 'बी1' कोटेनरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टेम्प्लेट ऑफ रिफरेंस (टीओआर) पीपर ई.आई.ए./ई.एन.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायर्समेंट क्लीयरेंस अप्रैल ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इन्फ्रस्ट्रक्चर (फेसल एण्ड नॉन फेसल) हेतु टीओआर जारी किया गया है।

सदामुख्य परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. धरतीसमूह के पत्र दिनांक 03/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बीठक का विवरण -

(अ) समिति की 480वीं बीठक दिनांक 10/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुरेश कुमार अग्रवाल, चार्टर्डर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स चायोमीर इन्व्हायर्स लेबोरेटरी एण्ड कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ठेकराबाद की ओर से श्री नंदरवर रेड्डी उपस्थित हुए। समिति द्वारा मसूची, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी -

- निकटतम आवादी ग्राम-पाली 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन किलोहीमल नगर 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राजमार्ग 2.8 कि.मी. दूर है। बेंगो नदी 2.5 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
- उर्वरता आरक्षित वन 600 मीटर, लक्ष्य आरक्षित वन 2.3 कि.मी., तटबंधित आरक्षित वन 2.6 कि.मी. एवं बरकाजगर आरक्षित वन 3.2 कि.मी. की दूरी पर है।
- लाखा संरक्षित वन 1.7 कि.मी., छारिबुंगरी संरक्षित वन 3.8 कि.मी., दुवावानी संरक्षित वन 4.4 कि.मी., कंराडुंगरी संरक्षित वन 5.5 कि.मी., बरिला संरक्षित वन 6.3 कि.मी., पूजीपारा संरक्षित वन 6.6 कि.मी., विरवानी संरक्षित वन 7.1 कि.मी., जुनवानी संरक्षित वन 7.6 कि.मी. एवं पझर संरक्षित वन 8.7 कि.मी. की दूरी पर है।

2. लेण्ड यूज फटेमैट -

S.No.	Land use	Area (in Ha.)	Area in %
1.	Plant Area	1.20	21.8
2.	Raw Material Storage yard	0.50	9.0

3.	Product Storage yard	0.40	7.2
4.	Solid Waste Storage yard	0.30	5.4
5.	Internal Roads	0.50	9.0
6.	Greenbelt Area	1.83	33.0
7.	Water Reservoir and RWH	0.10	1.8
8.	Parking Area	0.70	12.6
	Total	5.53	100

3. **पू-स्वामित्व** – भूमि के सभी विनियमक आवरण एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज के नाम पर है। पार्टनरशिप डीज की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार श्री जलम कुमार अग्रवाल, श्री पुष्कर लाल अग्रवाल एवं श्री सुरेश कुमार अग्रवाल पार्टनर हैं।

4. **है-मटेरियल** –

S.No.	Raw Material	Quantity (in TPA)	Sources	Mode of Transport
1.	DRI Kiln (Sponge Iron) - 62,700 TPA			
a)	Iron ore	1,00,320	Barbil, Odisha NMDC, CG	By Rail & Road (Through Covered Trucks)
b)	Coal	Indian	SECL CG / MCL Odisha	By Rail & Road (Through Covered Trucks)
		Imported	Indonesia / South Africa / Australia	Through Sea Route, Rail & Road
c)	Dolomite	3,135	Raigarh	By Road (Through Covered Trucks)
2.	FBC Boiler (Power Generation) - 5 MW			
a)	Indian Coal	53,400	SECL CG / MCL Odisha	By Rail & Road (Through Covered Trucks)
			OR	
b)	Imported Coal	34,268	Indonesia / South Africa / Australia	Through Sea Route / Rail / Road
			OR	
c)	Dolochar	18,100	In Plant Generation	Through Covered Conveyors
	Indian Coal	44,055	SECL CG / MCL Odisha	By Rail & Road (Through Covered Trucks)
			OR	
d)	Dolochar	18,100	In Plant Generation	Through Covered Conveyors
	Imported Coal	24,863	Indonesia / South Africa / Australia	Through Sea Route / Rail / Road

5. **प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी** –

S. No.	Unit (Product)	Capacity
1.	DRI Plants (Sponge Iron)	2 x 95 TPD (62,700 TPA)
2.	Power Plant	WHRB Based 5 MW (2 x 13.5 TPH)

(electricity)	FBC Based	8 MW (1 x 36 TPH)
---------------	-----------	-------------------

6. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – परियोजना हेतु डीआरआई किर्न के साथ उच्चतम एमआरबी आधारित पीपर फ्लांट में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु एलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेसिपिटेटर (ESP) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। एकबीसी बीपलर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु एलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेसिपिटेटर (ESP) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। सभी ट्रांसफर थ्रोइंग्स, अशिम ड्रकॉई, आदि से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु ड्राई पॉपिंग सिस्टम के साथ बैग फिल्टर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। सभी चिमनीयों से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। एल.ओ.₂ की उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाने हेतु स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग ड्रकॉई स्थापित की जाएगी। एन.ओ.एक्स (NOx) बॉर में कमी हेतु तीन क्लरीफ कम्बलन, फ्लू गैस रिसावकट्रोलेशन एवं ऑटो कन्वर्शन कंट्रोल व्यवस्था का उपयोग किया जाएगा। चिमनी की ऊंचाई की समता कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार डीआरआई किर्न हेतु प्रस्तावित चिमनी की ऊंचाई 50 मीटर तथा एकबीसी बीपलर हेतु प्रस्तावित चिमनी की ऊंचाई 81 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है।

7. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

Waste	Quantity (In TPA)	Disposal
Ash from DRI Kiln	11,286	Will be given to brick manufacturers
Dolochar	18,180	Will be used in FBC power plant as fuel
Kiln Accretion Slag	554	Will be used in road construction and given to brick manufacturer
Wet Scrapper Sludge	2,884	Will be used in road construction and given to brick manufacturer
Ash from power plant (with Indian coal + dolochar)	31,110	Ash generated is being given to cement Plants / brick Manufacturers

8. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- जल खपत एवं स्त्रोत – परियोजना हेतु कुल 340 घनमीटर जल प्रतिदिन (डीआरआई किर्न में 50 घनमीटर प्रतिदिन, पीपर फ्लांट में 280 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग टॉवर मेकअप में 135 घनमीटर प्रतिदिन, बीपलर मेकअप में 101 घनमीटर प्रतिदिन एवं डीएम रिजलरेशन में 44 घनमीटर प्रतिदिन) तथा घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। नू-जल जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ड्राफ्ट वॉटर अथॉरिटी से 340 घनमीटर प्रतिदिन हेतु अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जिसकी फाइन दिनांक 25/08/2025 तक है।
- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उपचार होगा। डीआरआई किर्न से उत्पन्न जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग (Closed circuit cooling system) हेतु उपयोग में लाया जाएगा। प्रस्तावित पीपर फ्लांट से दूषित जल की मात्रा 114 घनमीटर प्रतिदिन (पीपर फ्लांट से 108 घनमीटर

प्रतिदिन (कुलित टॉवर ब्लोडाउन से 34 घनमीटर प्रतिदिन, बीधलर ब्लोडाउन से 28 घनमीटर प्रतिदिन एवं डीएम रिजर्वेशन से 44 घनमीटर प्रतिदिन) तथा सेनेट्री उपयोग से 8 घनमीटर प्रतिदिन) उपलब्ध होगा। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. (न्यूट्रिजेंट्स रिमूवल सिस्टम) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना से पहले दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित लीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (क्षमता 8 घनमीटर) की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्स्रावण की स्थिति रखा जाना प्रस्तावित है।

- **शून्य-जल उपयोग प्रबंधन** - परियोजना स्थल सेंट्रल प्राइमरी वाटर बोर्ड की अनुसार सेक जॉन में आता है। जिसके अनुसार-

(अ) गृह एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःसंचयन एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) प्राइमरी वाटर सिंचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल सिंचार्ज के अन्तर्गत पर शून्य-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल प्राइमरी वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** - उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल संचयन 39,942.03 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 12 मम सिंचार्ज स्ट्रक्चर (आवा 4 मीटर एवं लंबाई 24 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पर्याप्त परिसर के पूर्ण संचयन को सिंचार्ज किया जा सकेगा। सभी सिंचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का संग्रह हो सके।

8. **विद्युत आपूर्ति स्थिति** - परियोजना हेतु 24 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। कन्सट्रक्शन फेज के दौरान विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। प्रस्तावित कार्यकाल के दौरान विद्युत की आपूर्ति क्वॉटिब प्लांट क्षमता 14 मेगावॉट (एकबीसी आधारित 8 मेगावॉट एवं डब्ल्यूएचआरबी आधारित 8 मेगावॉट) से की जाएगी।

10. **कुसारापन संबंधी जानकारी** - प्रस्तावित परियोजना से हरित घटितका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 1.83 हेक्टर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित उद्योग परिसर के घेरे और 15 मीटर की मोटाई में कुसारापन किया जाएगा। समिति का मत है कि पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुखा हेतु बेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-

1. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** - मॉनिटरिंग कार्य 15 अक्टूबर 2021 से 15 जनवरी 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर शून्य-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

(Handwritten signature)

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का सामान्य लेवल:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	22.5	52.5	50
PM ₁₀	48.6	87.5	100
SO ₂	11.9	26.9	80
NO ₂	13.8	39.3	80

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:- ई.आई.ए. के Chapter Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार फ्लोनाइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लोड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सामान्य लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	45.2	55.9	75
Night L _{eq}	37.1	43.6	70

जो उच्च श्रेण के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की गणना:- जारी वाहनों / क्वार्टीएवशल हेवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 794 पी.सी.यू. प्रतिघंटा है। प्रस्तावित परियोजना उपरंत 40 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। उत्पात्ताद कुल 834 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (V/C ratio) 0.556 होगी। विस्तार के उपरांत पी री-मटेरियल / ड्रॉवकट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Good 0.4 to 0.6) के भीतर है।

12. वन्यजन्ती संरक्षण योजना - 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना बचे जाने के कारण कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजन्ती एवं जीव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यजन्ती अभिक्षाक के आदेश क्रमांक व.प्र. / प्रत्ये-575/119 नका सयपुर दिनांक 27/08/2022 के द्वारा रुपये 49 लाख (5 वर्ष में) की वन्य प्राणी संरक्षण योजना के अनुमोदन उपरंत प्रस्तुत की गई है। वन्य प्राणी संरक्षण योजना में प्रास्तावित राशि रुपये 49 लाख (5 वर्ष में) एकमुश्त जमा करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को आवेक्षित किया गया है। समिति का मत है कि वन्यप्राणीयों के संरक्षण हेतु तैयार पांच वर्षीय योजना की राशि बहुत कम प्रतीत हो रही है, वृत्तीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में राशि बहुत ही कम प्रस्तावित है, जिसे और बढ़ाया जाये। वन क्षेत्र के समीप उद्योग स्थापना से इसके सिस्टम को जितना सजात आघात लगता है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती फिर भी प्रतिवर्ष प्रस्तावित राशि, कुल प्रोजेक्ट लागत को दृष्टिगत रखते हुये वन्यप्राणी संरक्षण कार्यों की आवश्यकता के अनुकूल हो। प्रस्तावित लीड उद्योग आवेक्षित एवं संरक्षित वनों से घिरा हुआ है और यह वन, हाथियों तथा अन्य वन्य प्राणीयों के स्थायी आश्रय एवं रहनास स्थल है, जहां सदैव वन्यजन्ती आश्रय पाते हैं। किसी उद्योग की आयु कम से कम 30 वर्ष नानी गई है। इससे अधिक भी हो सकती है। यह उद्योग 24 घंटे और वर्षभर कार्यरत रहेगा। इसकी फलस्वरूप पर्यावरण पर प्रभाव भी सजात बना रहेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा

21

प्रारंभिक चरण में 5 वर्षों की वन्यप्राणी संरक्षण योजना तैयार कर प्रस्तुत की गई, उसके पश्चात् उद्योग की आयु (30 वर्ष) तक प्रत्येक 5 वर्ष में "सुन-संशोधित वन्यप्राणी संरक्षण योजना" तैयार कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ताकि वन्य प्राणीयों के रहवास ननों को उद्योग के मिट्टी, जल, वायु ध्वनि एवं प्रकाश को प्रदूषण जनित प्रतिकूल प्रभावों से एवं उद्योग जनित अत्यधिक जैविक दबाव से संरक्षित किया जा सके। उद्योग जनित तापक्रम बढ़ने से जंगलों में आग लगने की घटनाएँ भी होती हैं।

वन्यप्राणीयों की समुचित सुरक्षा, संरक्षण, प्रबंधन एवं उनसे रहवास का संरक्षण एवं प्रबंधन एक बार (one time) किये जाने वाला कार्य नहीं है और न ही यह केवल 5 वर्ष का कार्य है। बल्कि यह सतत किये जाने वाले कार्य है और जब वन्यप्राणीयों का स्थायी रहवास औद्योगिक प्रदूषण से सतत प्रभावित हो रहा हो तो और अधिक गहन वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन (Intensive Wildlife Conservation and Management) की सतत आवश्यकता होती है। इसी तरह प्रदूषित वातावरण में उनके रहवास की भी गहन संरक्षण एवं प्रबंधन (Intensive Habitat Protection, Conservation & Management Plan) योजना की सतत आवश्यकता होती है।

दीर्घ अवधि की वन्यप्राणी संरक्षण योजना के अभाव में दीर्घ अवधि की पर्यावरणीय स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं होगा। प्रत्येक 5 वर्ष पूर्व होने के एक वर्ष पूर्व आगामी 5 वर्षों के लिए "समुचित वन्यप्राणी संरक्षण प्रबंधन योजना" तैयार कर विधिवत् रखन प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर संरक्षण योजना की तकि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़ से नरामर्ग उपरांत "राज्य कैम्पा फंड (State CAMPA Fund)" में जमा की जाएगी। इस आसय का समय पत्र (Affidavit) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जाए। इसके पश्चात् ही आगामी कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

13. लोक सुनवाई दिनांक 11/01/2023 प्रातः 11:00 बजे स्थान - कंजारी मंदिर की लीन का मैदान, घाम-लटाईमाल, तहसील-घरपोडा, जिला-रायगढ़ में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य संघिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 23/03/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।

14. जनसुनवाई के दौरान 300-400 लोग उपस्थित हुये। उपस्थित सभी जनसमुदाय द्वारा प्रस्तावित उद्योग का समर्थन किया गया है।

15. लोक सुनवाई शिथी के पूर्व लिखित रूप से 8 अन्यायेदन प्राप्त हुये है, जिसमें निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

1. प्रस्तावित उद्योग से आस-पास के मातस्य कुषकों के ताताओ/कैली जलाशय क्षेत्र में दूषप्रभाव पड़ेगा।

2. इस उद्योग द्वारा स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं दिया गया है और ना किसी प्रकार का विकास कार्य में कार्य किया गया है। उद्योग से निकलने वाली प्रदूषण से खेत बर्बाद हो गया है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की क्षीर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-

[Handwritten Signature]

1. बंगला नदी 2.5 कि.मी., समिपत्य लाताव 4.4 कि.मी. एवं मेरवाणी नाला 2.5 कि.मी. की दूरी पर ही प्रस्तावित स्थल से कोई नदी नाला नहीं गुजरता है।
2. उद्योग में वायु प्रदूषण को रोकथाम के लिए एलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेसिपिटेटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखी जाएगी। औद्योगिक दूषित जल को उपचार हेतु ई.टी.पी. स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। परंतु दूषित जल को उपचार हेतु सीकेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। शुद्ध निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

समिति का मत है कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिव्य जाने के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से वर्षा उपचार निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
11,000	Up to 100 Crores 2% & 100 Crores to 500 Crores 1.5%	215	Following activities at Village- Pak, Chiralpani & Lakha	

सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको-पार्क निर्माण" के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत लाखा के अश्विनी ग्राम चिरईपानी के खसरा क्रमांक 72 क्षेत्रफल 3.427 हेक्टेयर एवं ग्राम लाखा खसरा क्रमांक 204 क्षेत्रफल 17.244 हेक्टेयर क्षेत्र में ईको-पार्क निर्माण हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत की गई है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत देवारी के अश्विनी ग्राम पाली के खसरा क्रमांक 19 एवं 24 कुल क्षेत्रफल 8.487 हेक्टेयर क्षेत्र में ईको-पार्क निर्माण हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि ईको-पार्क निर्माण हेतु प्रस्तावित ग्रामों (ग्राम-चिरईपानी, लाखा एवं पाली) द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि के अनुसार कुल वृक्षों की गणना करते हुए प्रथम वर्ष में ही पौधों का रोपण (30 प्रतिवर्ग जीवन वन सहित), सुस्था हेतु बेसिंग, छाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्ष का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव मिन-मिन (ग्राम अनुसार) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित चरणों से निकटतम अवरक्षित वन, संरक्षित वन एवं अरिज एरिया की जानकारी हेतु वनमण्डल अधिकारी, रायगढ़ वन मण्डल, रायगढ़ को आवेदन किया गया है।
18. कार्यालय कार्यालयन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़ संभाग, रायगढ़ को हस्तगत क्रमांक- 4567/लक./2022-23 रायगढ़, दिनांक 14/07/2022 अनुसार उपर्युक्त प्रोजेक्ट क्षेत्र से निकटतम ग्राम पाली की सड़क मार्ग की दूरी 1.5 कि.मी. है।

19. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/वाचक/अदि. अ./2022 रायगढ़, दिनांक 18/08/2022 अनुसार प्रसारित प्रोजेक्ट से संबंधी गणदीक ग्राम घाटी की वायुमार्ग से दूरी 0.512 कि.मी. एवं सड़क मार्ग से दूरी 1.5 कि.मी. है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना जा.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई परस्पर विरोधी प्रकरण लंबित नहीं है।
22. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्या मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्य बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. स्थानीय लोगों को उनके योग्यता के आधार पर रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. प्रसारित परियोजना के तहत कुल क्षेत्रफल का 34.18 प्रतिशत क्षेत्र में पुनरोपवन किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) के तहत ईको-पार्क निर्माण हेतु प्रसारित घाटी (ग्राम-दिरईघानी, लारखा एवं घाटी) द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि को अनुसार कुल कूटो की गणना करते हुये प्रधान वर्ष में ही पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन वर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव विन-विन (ग्राम अनुसार) प्रस्तुत किया जाए।
3. हाथियों के संरक्षण हेतु तैयार 5 वर्षीय योजना की राशि बहुत कम प्रतीत हो रही है। कुत्तों, सर्पों एवं पंखे वर्ष में राशि बहुत ही कम है। वन क्षेत्र के स्वीय उद्योग स्थापना से ईको सिस्टम को जितना सतत आपात लगता है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती फिर भी प्रधान 5 वर्षों हेतु यह राशि कुल प्रोजेक्ट लागत को दृष्टिगत रखते हुये वन्यप्राणी संरक्षण कार्य की आवश्यकता के अनुरूप हो। अतः इस संबंध में प्रधान मुख्य वन सहायक (वन्य प्राणी एवं जैवविविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिक्षाक, धनवीरसाहू, नया रायपुर जटल नगर से पुनर्विधित/जागरूकता प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
4. उद्योग की आयु (Life of Industry) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए तथा इस आधार पर शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करे कि परियोजना प्रस्तावक उद्योग की आयु तक वन्यप्राणी संरक्षण योजना प्रत्येक 5 वर्ष में सदन प्राधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत करेंगे तथा निर्धारित राशि "राज्य वन्य नद (State CAMPA Fund)" में जमा करेंगे।

उपरोक्त बंझित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परिधीयता प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स मोहब्बत महिला स्वसहायता समूह, टेलगुड़ा खोसापटी, जख्ख-भीमली संगीता वील (टेलगुड़ा सेक्टर नार्थ-1), ग्राम-टेलगुड़ा, तहसील-वाठना, जिला-उत्तर बस्तर कार्फेर (सचिवालय का नक्सी क्रमांक 2504)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एलआईए/ सीजी/ एमआईएम/ 432129/ 2023, दिनांक 04/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गैंग खनिज) है। यह खदान ग्राम-टेलगुड़ा, ग्राम पंचायत मिलाई, तहसील-वाठना, जिला-उत्तर बस्तर कार्फेर स्थित प्लॉट ऑफ खसरा क्रमांक 1, कुल क्षेत्रफल-4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-69,825 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परिधीयता प्रस्तावक को एल.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के दायन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु सीमली संगीता वील, जख्ख (मोहब्बत महिला स्वसहायता समूह, टेलगुड़ा खोसापटी) उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्सी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मिलाई का दिनांक 15/02/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विन्दाकित/सीमकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्दाकित/सीमकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना - नार्थ प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो ग्राम-संचालक (ख.प्र.), जिला-उत्तर बस्तर कार्फेर के दायन क्रमांक 1045/खनिज/उत्ख.योजना/रेत/2023-24 उ.ब.कार्फेर, दिनांक 25/05/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कार्फेर के दायन क्रमांक 1060/खनिज/ख.ति./रेत/2023 कार्फेर, दिनांक 25/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कार्फेर के दायन क्रमांक 1059/खनिज/ख.ति./रेत/2023 कार्फेर, दिनांक 25/05/2023 द्वारा जारी

प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, रेल लाईन, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, दुकानें, मस्जिद एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. मोहल्ला महिला स्वसहायता समूह, टेलगुडा सोसायटी, अय्यल-धीमती संघीता वॉल के नाम पर है, जो कार्यालय कॉलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कॉलेज के द्वारा क्रमांक 988/खनिज/रेल/2023 कांकेर, दिनांक 18/05/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु वैध है। जारी एल.ओ.आई. में 'छातीसगढ़ ग्रीन खनिज सहायता रेल का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) विधम 2023 विधम 7 के तहत रेल खदान उत्खननयुक्त अवधि 5 वर्ष की स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों के पूर्ण हेतु यह आशय-यह जारी किया जा रहा है।' का उल्लेख है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वन मण्डलधिकारी, कॉलेज वन मण्डल, जिला-कॉलेज के द्वारा क्रमांक/वा.वि./2023/2550, कॉलेज दिनांक 08/04/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार अधिदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी पर है।
9. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-टेलगुडा 720 मीटर, स्कूल ग्राम-टेलगुडा 830 मीटर एवं अस्पताल कुरामा 1.1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 22.08 कि.मी. दूर है। रीढ़ पुल 540 मीटर, गाला 1.6 कि.मी., नहर 3.35 कि.मी. एवं तालाब 800 मीटर दूर है। स्वीकृत रेल खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट स्थित नहीं है।
11. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 203 मीटर, न्यूनतम 290 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई - अधिकतम 432 मीटर, न्यूनतम 431 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 125 मीटर, न्यूनतम 102 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी के मुहाने तट किनारे से दूरी अधिकतम 80 मीटर, न्यूनतम 38 मीटर है।
12. खदान स्थल पर रेल की मोटाई - आवेदन अनुसार स्थल पर रेल की गहराई - 4.05 मीटर तथा रेल खनन की प्रस्तावित गहराई - 1.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनिंग रेल की मात्रा-89,025 घनमीटर है। रेल उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेल सहाय की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेल की उपलब्ध औसत गहराई 4.05 मीटर है। रेल की वास्तविक गहराई हेतु पंथनाम प्रस्तुत किया गया है।
13. खदान क्षेत्र में रेल सहाय के लेवल - रेल उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुना 25 मीटर के पिंड सिन्दुरों पर दिनांक 17/05/2023 को रेल सहाय के वर्तमान लेवल (Levels) लेकर उन्हें खनिज

विभाग से प्रत्येकवर्ष उपरोक्त फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के गन्ना विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
27.36	2%	0.54	Following activities at nearby Village-Talguda	
			Plantation around Pond & AMC for 5 years	0.60
			Total	0.60

15. सी.ई.आर. की अंतर्गत राजाध के चारी और वृक्षारोपण हेतु (आम, जामुन आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 25 नग चौकी के लिए राशि 1,000 रुपये, पेंसिंग के लिए राशि 1,500 रुपये, खाद के लिए राशि 500 रुपये, सिंचाई तथा एक-रकबा आदि के लिए राशि 18,000 रुपये, कुल प्रकर प्रथम वर्ष में कुल राशि 18,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 42,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-तेलनुड़ा, ग्राम पंचायत तिलाई के सहमति उपरोक्त पंचायीय स्थान (ग्राम-तेलनुड़ा के खराब क्रमांक 608 एवं 609 में स्थित राजाध) के संक्षेप में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

16. वृक्षारोपण कार्य – नदी तट में 250 नग एवं पहुंच मार्ग में 250 नग (कुल 1,000 नग) वृक्षारोपण करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है, जो निम्नानुसार है:-

विवरण	प्रथम वर्ष (रुपये)	द्वितीय वर्ष (रुपये)	तृतीय वर्ष (रुपये)	चतुर्थ वर्ष (रुपये)	पंचम वर्ष (रुपये)
वृक्षारोपण हेतु परियोजना के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु जल छिड़काव	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
नदी तट एवं पहुंच मार्ग में (1,000 नग) वृक्षारोपण हेतु प्रतिशत जीवन दर	1,00,000	—	—	—	—
पेंसिंग हेतु राशि	1,50,000	—	—	—	—
खाद हेतु राशि	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
सिंचाई एवं	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000

रख-रखाव हेतु राशि					
अन्य लागत-साईन बोर्ड, रेडियम बॉय एवं अन्य आकस्मिक कार्य	5,000	-	-	-	-
कुल राशि = 15,05,000	5,05,000	2,50,000	2,50,000	2,50,000	2,50,000

17. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्लुओरिडिड वॉटर उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. खदान क्षेत्र की आस-पास नदी तट एवं पहुंच मार्ग में सभ्यन पुनारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सतवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्सर्जन का प्रकरण लंबित नहीं है।
23. स्थानीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. स्थानीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अनुमोदित उत्खनन योजना में दिए माईनेबल रिजर्व का 80 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जाएगा एवं खदान में तथा खनन के दौरान सस्टेनेबल सेड माईनिंग गाईडलाईन्स 2016 एवं इन्फोर्सींग एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स और शैपड 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

26. पर्यावरण स्वीकृति में दिखे गये शर्तों का पालन किये जाने एवं छत्रछाई पालन प्रतिवेदन पर्यावरण कार्यालय में जमा कराने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में पुष्करोपम कार्य के गैरनिर्धारित एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ऑनलाईन/प्रतिनिधि प्राप्त पंचायत को पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में पुष्करोपम का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
28. लीज क्षेत्र के बाहरी कोनों तथा सीमा लाईन के न्यून में सीमेंट को खम्भे लगाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी से स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
29. रेत उत्खनन वैज्ञानिक विधि से एवं भरवाई का कार्य लीडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लीडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भरवाई का कार्य वैज्ञानिक विधि से ही कराई जाये। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति नांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तलरांकी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। स्थानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (पान-तेलकुंड) का रकबा 4.8 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत ग्राह अध्ययन (Sitiation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय वनस्पति, लीज एवं सूखे ज़ीलों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
3. लीज क्षेत्र की सतह का रेसालाईन कटा —
 1. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., जलसंग्रह को प्रस्तुत किये जायें।
 2. फेब्रु-मार्च/अप्रैल/मई/जून माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं विभिन्न बिन्दुओं में गार्डेनियेन लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।
 3. इसी प्रकार रेत खनन उपरान्त मार्च/अप्रैल/मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं विभिन्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।

1b. रेत सतह को पूर्व निर्धारित रिड बिन्दुओं पर रेत सतह को लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य अगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। फेज-1-मानसून के आंकड़े वित्तवर्ष 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं फी-2-मानसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जाएंगे।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से मेसर्स ग्रीडवैबत महिला स्वयंसेवायता समूह, टेलगुड़ा बीमाघाटी, अध्यक्ष-बीमती संगीता पौल (टेलगुड़ा रोपब माईनिंग-1), प्लॉट ऑफ खसरा क्रमांक 1, ग्राम-टेलगुड़ा, तहसील-घासना, जिला-खारक बलार कांकेर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.8 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 44,100 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु परिसिस्ट-01 में वर्णित शर्तों के अधीन विदे जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई धनिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्लॉट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेली द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल रोपब माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर रोपब माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार खनन सुनिश्चित किया जाए।

6. इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर रोपब माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

संघ राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स बिसनपुर लाईन स्टोन क्वारी (जे-बी सुरेश अधवाल), ग्राम-बिसनपुर, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-भारंगढ़ (सविभाज्य का नस्ली क्रमांक 2505)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 432204/ 2023, दिनांक 04/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - पट्ट पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गोष्प खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बिसनपुर, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-भारंगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 234, कुल क्षेत्रफल-0.748 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-17,182.5 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 10/08/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अधूर्ण होने के कारण से

समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई व्यक्ति जानकारी एवं सम्बन्धित सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

7. मैसर्स शुभ मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, कार्यालय- श्री प्रदीप कुमार चौपल, ग्राम-सूमरपाच, तहसील-नया बाराहार, जिला-सक्की (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 2608)

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 432118 / 2023, दिनांक 08 / 08 / 2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित कोलोनार्डेट (बीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-सूमरपाच, तहसील-नया बाराहार, जिला-सक्की स्थित खसरा क्रमांक 2335 / 1, 2335 / 2, 2335 / 3, 2335 / 4, 2335 / 5, 2335 / 6, 2335 / 7, 2335 / 8, 2335 / 9, 2335 / 10, 2335 / 11, 2335 / 12, 2335 / 13, 2335 / 14 एवं 2335 / 15, कुल क्षेत्रफल-4883 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2,00,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., जलोसमद के ज्ञापन दिनांक 02 / 08 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 15 / 08 / 2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उत्खनन योजना - जारी प्लान एरिंग विध संघी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 887 / खनिज / स. पा.आ. / 2022-23 संख्या, दिनांक 01 / 05 / 2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सक्की के ज्ञापन क्र. 125 / बीम खनिज / न.क्र. / 2022-23 संख्या, दिनांक 05 / 04 / 2023 अनुसार ज्ञापित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 9 खदानें, क्षेत्रफल 485.784 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र / संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सक्की के ज्ञापन क्र. 124 / बीम खनिज / न.क्र. / 2023 संख्या, दिनांक 05 / 04 / 2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरुपट,

पुनः नदी, रेल लाइन, अस्पताल, स्कूल, एम्बेस्सी बस एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण – भूमि एवं एल.ओ.आई. सेक्टर गुप्त मिनेरल्स प्राइवेट लिमिटेड डीपरेण्डेन्ट की प्रतीका कुम्हार रोडजल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजी के ज्ञापन क्र. 73/गीप खनिज/न.क्र./2023 राजी, दिनांक 22/02/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी शेषता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमंडल अधिकारी, जांजगीर-बाघा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2022 बाघा, दिनांक 26/09/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 300 मीटर की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी दूनरपाच 1 कि.मी., स्कूल दूनरपाच 1 कि.मी. एवं अस्पताल नया बाघाद्वार 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2 कि.मी. दूर है। तालाब 1.4 कि.मी. दूर है।
10. पर्यावरण/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, सेन्टीनल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोइंटुटेड एरिया, पर्यावरण/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र का घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. खनन संवेदा एवं खनन का विवरण – जिपसोलॉजिकल रिजर्व 37,34,745 टन एवं माईनेबल रिजर्व 20,03,125 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 9,839.48 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर मात्र 32,048.8 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 से 8 मीटर होगी। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। लीज क्षेत्र में इमारत स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जीक डैमर, सीक ड्रेजिंग से डिड्रिंग एवं कंट्रोल बलैन्सिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नांकित है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,80,000
द्वितीय	1,80,000
तृतीय	2,00,000
चतुर्थ	2,00,000
पंचम	2,00,000

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति का स्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की फाटी में 1.805 नव वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा फाटी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा फाटी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. न्यूनतम एन.जी.टी., डिस्ट्रिक्ट बेंच, नई दिल्ली द्वारा तैयार माध्यम विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (सेरिजेशन एडिशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यलय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-सक्ती के ड्राफ्ट नं. 125/गीप खनिज/न.अ./2022-23 तारीख, दिनांक 06/04/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के वीर अवस्थित 9 खदानें, क्षेत्रफल 485.784 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (घाम-दूमरपास) का क्षेत्र 4.683 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घाम-दूमरपास) को मिलाकर कुल रकबा 490.467 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संघातित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कलस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायर्समेंट क्लीयरेंस अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीचे कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई—

- i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- iv. Project proponent shall submit the top soil/OS management plan & incorporate the details in the EIA report.
- v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

- vi. Project proponent shall submit the NOC of Gram Panchayat (alongwith its minutes of meeting) for Mining Activity.
- vii. Project proponent shall submit the details of water requirement along with its source and shall also submit a copy of NOC for usage of water from competent authority.
- viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- x. EIA study shall be done at minimum 10 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xiv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xv. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tall tree species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), कलकत्ता में उपरोक्त सूचित किया जाए।

8. वेसर्न अकलसच डीलोमाईट क्वारी (प्रो.-श्री रविश अग्रवाल), ग्राम-अकलसच, तहसील-जैजपुर, जिला-जाजगीर-बांधा (सचिवालय का नक्का क्रमांक 2334)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एमआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 421622/2023, दिनांक 10/03/2023 द्वारा टी.ओ.अर. हेतु आवेदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमिटी होने से ज्ञापन दिनांक 22/03/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्रिका जानकारी दिनांक 05/06/2023 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित डीजेलगाईट (गीण खनिज) खदान है। खदान प्लान-अकलसारा, तहसील-जैजपुर, जिला-जाजगीर-बांघा स्थित खसरा क्रमांक 880/2, 870/2, 871, 872/1, 872/2, 878, 883/2 एवं 884, कुल क्षेत्रफल-1.884 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-80,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री वैभव अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा सती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधि पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अकलसारा का दिनांक 15/05/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - खारी प्लान एरिया विथ क्वार्टी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक, संचालनालय सीमिटी तथा खनिज के ज्ञापन क्रमांक 264/सईनिंग-2/अयु.पी./एक.एन.05/2023 तथा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25/01/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सती के ज्ञापन क्र. 15/गीण खनिज/न.क्र./2022-23 सती, दिनांक 12/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 21.819 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सती के ज्ञापन क्रमांक 128/गीण खनिज/न.क्र./2023 सती, दिनांक 12/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, पुल, नदी, रेल लाइन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. की सही अग्रवाल के नाम पर है, जो छत्तीसगढ़ शासन, खनिज सार्वजनिक विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर के ज्ञापन क्र. एक 3-2/2019/13 नया रायपुर, दिनांक 12/10/2020 द्वारा जारी की गई है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि एल.ओ.आई. की वैधता पुष्टि कबल दिनांक 10/08/2023 को आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।
7. नू-स्वामित्व - भूमि श्री रितेश कुमार, श्री सुधीर कुमार, श्री प्रशांत कुमार, श्रीमती स्नेहा, श्रीमती सलू, श्रीमती सुशीला एवं श्री शिव कुमार के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनामलि प्रमाण पत्र – कार्यालय वनसंरक्षणविभागी, जालंधीर-घाम्वा वनमण्डल, घाम्वा के ड्राफ्ट क्रमांक/तक.अधि./1412 घाम्वा, दिनांक 28/02/2022 से जारी अनामलि प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी एवं स्कूल घाम-अकलसत 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 22 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11 कि.मी. दूर है। नाला 50 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतीवर्धित किया है।
12. खनन संवदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 14,78,585 टन, माईनेबल रिजर्व 8,72,189 टन एवं रिफ़रबल रिजर्व 8,28,580 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,400 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेबी मेकनार्ड्रज्ज विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 29.12 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.87 मीटर एवं नाला 8,588.4 घनमीटर है। लीज क्षेत्र में ओवर बर्डन की मोटाई 0.88 मीटर एवं नाला 9,338.92 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 13.8 वर्ष है। लीज क्षेत्र में प्रसार स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक ड्रमर ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्यारिस्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का चिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	40,000
द्वितीय	50,000
तृतीय	60,000
चतुर्थ	70,000
पंचम	80,000

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति का स्वोट एवं संबंधित विभाग से अनामलि प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 882 नव वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल सेक्टर, नई दिल्ली द्वारा सर्वेक्ष पाय्लेट भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ऑरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 डीए 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA, as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

शक्ति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय क्लस्टर (खनिज शाखा), जिला-सक्की के डायन ज. 15/गीण खनिज/म.ज./2022-23 सक्की, दिनांक 13/01/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 21.819 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (ग्राम-अकलसर) का रकबा 1.884 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-अकलसर) को मिलाकर कुल रकबा 23.703 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी ली गयी।

2. शक्ति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से प्रकरण 'बी1' कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्न ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम्.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिस्पायसिंग इन्वायर्नमेंट प्रोटेक्शन अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीचे कोल गाइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न जतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई:-

- i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.
- iv. Project proponent shall submit the LOI (letter of intent) extension copy.
- v. Project proponent shall submit the top soil & over burden management plan & incorporate the details in the EIA report.
- vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- vii. Project proponent shall submit the details of water requirement along with its source and shall also submit a copy of NOC for usage of water from competent authority.
- viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

- ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xi. Project proponent shall submit the copy of panorama and photographs of every monitoring station.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xiv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xv. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सुचित किया जाए।

- g. मेसर्स सिरी रोषद खारी (सचिव/सर्वेक्ष, ग्राम पंचायत सिरी), ग्राम-सिरी, तहसील-पसान, जिला-कोरबा (सचिवालय का नशी बर्नांक 2507)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 433489/2023, दिनांक 07/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गोण्ड खनिज) है। यह खदान ग्राम-सिरी, तहसील-पसान, जिला-कोरबा स्थित खसरा बर्नांक 21, कुल क्षेत्रफल - 3.036 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन बमनी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-18,210 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ में आपन दिनांक 03/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023-

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री वल्लभराम कर्गरी, सरपंच, ग्राम पंचायत सिरौली उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. घुई में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को घुई में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — रेल परखमन को संबंध में ग्राम पंचायत सिरौली का दिनांक 07/12/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विन्दाकिरा/सीन्दाकिरा — कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्दाकिरा/सीन्दाकिरा कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना — माईन प्लान विथ सेफ्ट रिक्विजिटमेंट एण्ड इन्वेलपमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरबा के द्वारा क्रमांक 1026/खनिज/उ.प्रा.ख./2023-24 कोरबा, दिनांक 25/05/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरबा के द्वारा क्रमांक 1024/खनिज/2023 कोरबा, दिनांक 25/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेल खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरबा के द्वारा क्रमांक 1024/खनिज/2023 कोरबा, दिनांक 25/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मस्जिद एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण — एल.ओ.आई. सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत सिरौली के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरबा के द्वारा क्रमांक 1016/खनिज- /2023 कोरबा, दिनांक 23/06/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है। जारी एल.ओ.आई. में "छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज साधारण रेल का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम 2023 के तहत आवेदित भूमि में ग्रीन खनिज साधारण रेल हेतु उत्खननपट्टा विलेख के पंजीयन दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्खननपट्टा स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों के पूर्ति हेतु यह आवास-पत्र जारी किया जा रहा है।" का उल्लेख है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कटघोरा वन मण्डल कटघोरा, जिला-कोरबा के द्वारा क्रमांक/उ.प्रा.खि./2023/2416 कटघोरा, दिनांक 13/04/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र कक्षा से 1 कि.मी. की दूरी पर है। आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की संख्या 3 लग है।
9. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आबादी ग्राम-सिरौली 1.2 कि.मी., स्कूल एवं अस्पताल पसान 14.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 कि.

मी. एवं राजमार्ग 14 कि.मी. दूर है। रीढ़ पुल 3.8 कि.मी. एवं तालाब 840 मीटर दूर है। शीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनोकाट स्थित नहीं है।

11. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 138 मीटर, न्यूनतम 48 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 824.8 मीटर, न्यूनतम 576 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 82 मीटर, न्यूनतम 19.4 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी के तट किनारे से दूरी अधिकतम 41.7 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है।

समिति द्वारा पाया गया कि जिस खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई 138 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 41.7 मीटर है तथा खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई 48 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 10 मीटर है। जल रीढ़ माईनिंग क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 2.32 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुसूचित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा- 18,210 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 2.32 मीटर है एवं जल स्तर 3 मीटर की गहराई तक प्राप्ता हुआ। किये गये गड्ढे नीचे भी पर्याप्त रेत उपलब्ध है। रेत की वार्षिक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

13. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलिंग – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल में 28 मीटर तथा 28 मीटर की सिंग विन्दुओं पर दिनांक 10/08/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवलिंग (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से वर्षा उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
28.968	2%	0.579	Following activities at nearby	
			Pavitra Van Niman	0.579
			Total	0.579

सीईआर के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (बड़, नीम, पीपल, बेल, आंवला, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 वग पैथी के

लिए राशि 5,000 रुपये, कंसिंग के लिए राशि 20,438 रुपये, खाद के लिए राशि 1,500 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 5,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 31,938 रुपये तथा अगामी 4 वर्षों में कुल राशि 20,000 रुपये हेतु घटककार भंड्य का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत सिरी के सहमति अवगत क्यायोग समान (खसत क्रमांक 21/1/क, क्षेत्रफल 0.963 हेक्टेयर) के संके में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

16. वृक्षारोपण कार्य - नदी तट में 550 नम एवं पट्टुय मार्ग में 200 नम (कुल 750 नम) वृक्षारोपण करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है, जो निम्नानुसार है-

विवरण		प्रथम वर्ष (रुपये)	द्वितीय वर्ष (रुपये)	तृतीय वर्ष (रुपये)	चतुर्थ वर्ष (रुपये)	पंचम वर्ष (रुपये)
प्रयुक्त निरंतरता हेतु परियोजना के दौरान सड़की/पट्टुय मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल सिंचनाय		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
नदी तट एवं पट्टुय मार्ग में (750 नम) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	22,500	2,250	240	-	-
	कंसिंग हेतु राशि	32,500	-	-	-	-
	खाद हेतु राशि	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	सिंचाई हेतु राशि	5,000	5,000	5,000	3,755	3,755
कुल राशि = 1,65,000		77,000	24,250	22,240	20,755	20,755

16. खदान क्षेत्र के आस-पास नदी तट एवं पट्टुय मार्ग में लगन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सारवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. उत्तीर्ण आदर्श पुनर्वास नीति के तहत राष्ट्रीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण दस के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

19. लीज क्षेत्र के बाहर उत्खनन कार्य नहीं किये जाने हेतु राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार,

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.जा. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लक्षित नहीं है।

21. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 की common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बाबत अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
22. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 की writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि अनुमोदित उल्लंघन योजना में दिए सर्टिफिकेट रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उल्लंघन किया जाएगा एवं खदान में तथा खनन के दौरान सस्टेनेबल सोड गाइडिंग गाइडलाइन्स 2018 एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सेक्टर 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
24. सीईआर कार्ड एवं नदी लॉट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रोपसाईटर/प्रतिनिधि, वन विभाग के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं नदी लॉट में वृक्षारोपण पर कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
25. रेत उल्लंघन मैन्युअल विधि से एवं भरवाई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी बाहन की श्रेणी के है। अतः भरवाई का कार्य मैन्युअल विधि से ही कराई जावे। भारी बाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उल्लंघन की अनुमति नहीं है। अनुमोदित उल्लंघन योजना में उल्लंघन किन्तु जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तलाकड़ी आकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। इसी नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (घाम-सिरी) का रकबा 3.035 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान की-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आभासी 1.5 वर्ग मी किस्तुत मात्र अध्ययन (Situation Study) करावेगा ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उल्लंघन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंपर्क, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उल्लंघन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
3. जीव क्षेत्र की सतह का बेसलाइन डाटा —

- i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने से पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसकी आंकड़ें एम्.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।
 - ii. पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने से पूर्व) इन्हीं विभिन्न बिन्दुओं में माइनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक लम्बा खनन लीज के बहार / नदी तट (दीर्घी ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।
 - iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरोक्त मानसून के पूर्व (मई माह की अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं विभिन्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
 - iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन का कार्य आगामी 8 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून के आंकड़ें अप्रैल 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एम्.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
4. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के उपरोक्त सरत क्रमांक 16 से 23 तक के सपथ पत्र (Notarized undertaking) को एम्.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुमति की जाती है।
 5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से गैरार्थ सिटी रोन्ड क्वारी (सचिव/सचय, ग्राम पंचायत सिटी), खसर क्रमांक 21, ग्राम-सिटी, ताडसील-पसान, जिला-कोरबा, कुल लीज क्षेत्रफल 3.035 हेक्टेयर में उत्खनन हेतु रेत क्षेत्र का कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 18,210 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निर्धारण की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-02 में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी जड़कों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) में लॉन्ड्रिंग प्लांट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
 6. सस्टेनेबल रोन्ड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर रोन्ड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
 7. इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर रोन्ड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) की लक्ष्य 80 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एम्.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

10. मेजरस बुनकट्टा ज़ाईन स्टोन माईन (जे- श्री विकास अडवाला), ग्राम-बुनकट्टा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (सकिलालय का नक्सी क्रमांक 1850)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजित नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 69690/2021, दिनांक 07/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजित नम्बर - एसआईए/सीजी/एमआईएन/432384/2023, दिनांक 08/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति करने के लिए फाईनल ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित बुन पथर (पीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बुनकट्टा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग स्थित प्लॉट ऑफ खसरा क्रमांक 49, 50, 51, 52 एवं 53/1, कुल क्षेत्रफल-1.88 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-19.950 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/04/2022 द्वारा प्रकरण 'बी' कोटेगी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्न ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वियरमेंट प्रसीयुरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विकास अडवाला, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेजरस पी एच एन शीलकुमर, नौराज, उल्लासदेवा की ओर से श्री सुभाष कुमार उपस्थित हुए। उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्सी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बुनकट्टा का दिनांक 01/10/2021 को प्रस्ताव परित किया गया एवं दिनांक 10/10/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - कच्ची प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संपुजा-संचालक (स.स.), संचालनालय, सीमिजी एचए खनिज, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 4818/खनि 02/सं.प्ला. अनुमोदन/न.स.स.08/2020(2), नया रायपुर, दिनांक 08/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कर्वाला कलेक्टर (खनिज सहाय), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1148/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 28/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 25 खदानें, क्षेत्रफल 41.458 हेक्टेयर है। साथ ही उक्त जारी पत्र अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य 2 खदानों को अज्ञात पत्र जारी किया गया है, जिसका क्षेत्रफल 4.82 हेक्टेयर है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1148/खनिज.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 28/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एपीस्ट, राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. श्री विकास अग्रवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 162/खनिज/स.प./2021 दुर्ग, दिनांक 22/05/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी शिकायत जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ. आई. की शिकायत पृष्ठि बाबत न्यायालय सहायक, नौमिकी तथा खनिकर्मी तथा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 81/2022 द्वारा जारी पारित आवेदन दिनांक 09/11/2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौम खनिज विनियम, 2015 के नियम 42(5) परन्तु के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला दुर्ग को प्रत्यावर्तित किया जाऊ है।" होना बताया गया है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 49 श्री प्रभात शंकर अग्रवाल, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 50 श्री तुलसी राम मिश्रा, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 51 श्री रामु दयाल मिश्रा, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 52 हरी शंकर मिश्रा एवं पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 53/1 श्री अनीत कुमार सिंघल तथा श्री अम्बर कुमार सिंघल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामिनों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनाधिकृत प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2020/4817 दुर्ग, दिनांक 03/12/2020 से जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 50 कि.मी की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-बुनकट्टा 400 मीटर, स्कूल ग्राम-बुनकट्टा 400 मीटर एवं अस्पताल सेलुड 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कि.मी. एवं राजमार्ग 1 कि.मी. दूर है। तालाब 200 मीटर एवं खारुन नदी 19 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित विविधता संवेदनशील एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संभव एवं खनन का विवरण - जिब्रोलीजिकल रिजर्व 7,94,365 टन, माइनेकल रिजर्व 1,68,770 टन एवं निकलकैबल रिजर्व 1,51,893 टन है। लीज की

7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4.124 वर्गमीटर है। औपम कास्ट सेमी पैकेनाईज्ड सिंथी से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 24 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं माऊ 2.888 घनमीटर है जिसमें से 1.275 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (भाईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फेंकाकर कुआरोपन के लिए उपयोजित किया जाएगा एवं क्षेत्र 1.393 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को गैर माईनिंग क्षेत्र में संरक्षित कर रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संरक्षित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में कठोर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लॉस्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	19,950
द्वितीय	19,950
तृतीय	19,950
चतुर्थ	20,040
पंचम	19,950

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.88 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बीरबल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाधत सैन्ट्रल कार्बन कालर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. **कुआरोपन कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 822 नम कुआरोपन किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है—

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
खदान के बाउण्ड्री में (822 नम) कुआरोपन हेतु	कुआरोपन हेतु राशि	78,832	8,232	8,232	8,232	8,232
	फेंसिंग हेतु राशि	1,77,600	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	8,180	830	830	830	830
	सिंचाई हेतु राशि	1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000
	रख-रखाव हेतु राशि	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000
कुल राशि = 13,71,160		4,79,712	2,22,862	2,22,862	2,22,862	2,22,862

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4.124 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 720 वर्गमीटर क्षेत्र 10.5 मीटर की गहराई तक एवं 424 वर्गमीटर क्षेत्र 7.5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित कठरी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों पर उत्खनन है। सन्तिता का मत है कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अतिरिक्त उत्खनन किया जाना पावे जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

साथ ही समिति का यह भी मत है कि उक्त उल्लिखित क्षेत्र (अतिथिगत 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी) के पुनर्भरण हेतु रिस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ग्रीन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 5(1)(b) के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माइन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सीफ्टी जोन में कृषालेखन किया जाना आवश्यक है।

17. गैर माइनिंग क्षेत्र – लीज क्षेत्र में 1,780 वर्गमीटर क्षेत्र को पूर्ण रूप से प्रस्तावित अधिकांश गहराई तक गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है तथा 853 वर्गमीटर क्षेत्र को 10.5 मीटर की गहराई, 824 वर्गमीटर क्षेत्र को 18.5 मीटर की गहराई, 379 वर्गमीटर क्षेत्र को 7.5 मीटर की गहराई एवं 3,372 वर्गमीटर क्षेत्र को 15 मीटर की गहराई तक उल्लिखित करने के पश्चात् गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्लारी प्लान में किया गया है।

18. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण—

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य मार्च 2022 से मई 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

- ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का सान्द्रण लेवल—

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM ₁₀	26.28	43.58	50
PM _{2.5}	47.2	86.5	100
SO ₂	9.06	14.63	80
NO ₂	11.33	20.24	80

- iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता— ई.आई.ए. के Chapter Description of environment में दशदि गढ़े लेवल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

- iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)

Day L_{avg}	49.54	61.23	75
Night L_{avg}	40.67	52.41	70

जो उच्च क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

५. पीसीयू की गणना- नयी वाहनों / मल्टीएवजल हेवी वाहनों को समाहित करते हुए ट्रेफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 1,830 पीसीयू प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (V/C ratio) 0.122 है। प्रस्तावित परिवर्धना उपरान्त 192 पीसीयू की वृद्धि होगी। तत्परन्तु कुल 2,022 पीसीयू प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (V/C ratio) 0.14 होगी। विस्तार के उपरान्त भी सी-स्टेरिडल/ड्रोइवट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोक डीमिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

19. लोक सुनवाई दिनांक 11/01/2023, अपरान्त 12:00 बजे, स्थल - आदिवासी सामुदायिक भवन, ग्राम-बुनाकट्टा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई प्रस्तावक सदस्य सहित छातीसमूह पर्यावरण संरक्षण मंडल, तथा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 18/03/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।

20. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दाय/विचार प्रस्तुत किये गये हैं-

- खदान से बस्ती लगा हुआ है एवं बस्ती का आंगनबाड़ी कुछ दूरी पर है।
- खदानों से डस्ट उत्सर्जन होता है।
- खदान से बस्ती जग होने के कारण ब्लारिस्टिंग से अत्यधिक परेशानी होती है।
- स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है-

- लोक के पास जो आंगनबाड़ी है, ग्राम पंचायत जैसे ही जमीन देगी, खदान के चालू होने के पूर्व इन आंगनबाड़ी के लिए नये डिजाइनिंग का निर्माण करावेगी।
- डस्ट उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु लोक क्षेत्र के चारों ओर प्रथम वर्ग में ही फेंसिंग कराकर दूधानेपन किया जाएगा। साथ ही कच्ची सड़क पर जल छिड़काव किया जाएगा।
- ब्लारिस्टिंग का कार्य अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक द्वारा निम्न स्तर पर दिन में एक बार की जाएगी। साथ ही ब्लारिस्टिंग के पूर्व हुटर द्वारा सूचित किया जाएगा।
- खदान में काम करने के लिए स्थानीय हस्तशिल्पी को प्राथमिकता दी जाएगी।

21. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुए क्लस्टर में कुल 28 खदानें आती हैं। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है-



विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
पट्टीय मार्ग (10 कि.मी.) के दोनों तरफ (8,887 मग) कृषासेवा हेतु	कृषासेवा (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	5,00,000	50,618	50,618	50,618	50,618
	ट्री-प्लांट हेतु राशि	61,33,600	-	-	-	-
	खाद हेतु राशि	50,010	5,010	5,010	5,010	5,010
	सिंचाई हेतु राशि	12,00,000	12,00,000	12,00,000	12,00,000	12,00,000
	रख-रखाव हेतु राशि	9,60,000	9,60,000	9,60,000	9,60,000	9,60,000
कुल राशि = 1,77,12,808		68,50,302	22,15,628	22,15,628	22,15,628	22,15,628

सीमम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
पट्टीय मार्ग (248 मीटर) के दोनों तरफ (232 मग) कृषासेवा हेतु	कृषासेवा (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	17,632	1,748	1,748	1,748	1,748
	ट्री-प्लांट हेतु राशि	2,13,600	-	-	-	-
	खाद हेतु राशि	1,740	180	180	180	180
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	74,973	74,973	74,973	74,973	74,973
	कुल राशि = 8,17,549	3,08,945	76,901	76,901	76,901	76,901

22. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समस्त विस्तार से चर्चा समस्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
58	2%	1.32	Following activities at nearby, Village-Chunkatta	
			Pavitra Van Nirman	12.19
			Total	12.19

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (नीबू, आम, कंजक, कदम, जायफल, आंवला, अमलतास, बड़, पीपल आदि) कृषासेवा हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 228 मग पीपल के लिए राशि 17,176 रुपये, कंजक के लिए राशि 1,02,800 रुपये, आम के लिए राशि 1,710 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि

के लिए राशि 2,26,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,47,888 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,71,712 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्रान पंचायत पुनर्कट्टा द्वारा श्री विकास अडवाला, कुल लीज क्षेत्रफल 3.08 हेक्टेयर एवं श्री विकास अडवाला, कुल लीज क्षेत्रफल 1.88 हेक्टेयर को सी.ई.आर. के अंतर्गत परिवर्तन वन निर्माण हेतु खसरा क्रमांक 404 के क्षेत्रफल 0.31 हेक्टेयर में सहन्यति प्रदान की गई है।

24. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुए जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
25. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध करारकर जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
26. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अज्ञात एवं पेटेंटल सहित नक्शे में दर्शाते हुए पुनर्व्यक्ति कर प्रस्तुत किया गया है।
27. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रत्यक्षक द्वारा बताया गया कि यह एक नवीन खदान है, जो पूर्व से ही अस्तित्व में है। इस संबंध में समिति का मत है कि उक्त अस्तित्व क्षेत्र (अतिरिक्त 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी) के पुनर्भरण हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
29. लोकमान्यवर्ष के दौरान उठाये गये समस्त आस्थापन पूर्ण किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. अतीसमझ अदरों पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के तहत लय की गई राशि का उपयोग पर्यवेक्षण के हित में किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
32. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में सीसिंग कराकर वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले वृक्षारोपण तथा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यों की जानकारी गिपोटिंग (Geotag) फोटोग्राफस सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
33. प्लानिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अभिवृत्त डिप्लोमेटिक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
34. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुल्लेख न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भरण में किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

35. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर स्थान कुशासन किये जाने एवं रोपित पौधों का सम्पाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री विल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्खनन का प्रकरण लंबित नहीं है।
39. पवित्र में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन समाप्त हो अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
40. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
41. फ्यूजिटिव अक्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु निर्दिष्ट जल डिफ़्लक्स किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
42. आवेदित क्षेत्र में स्थित कुओं की प्रकृतियों की जानकारी प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही जल कुओं की आवश्यकता पड़ने पर ही कटाई स्थान प्राधिकारी से अनुमति उपरोक्त ही किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
43. सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले कुशासन का 66 वर्षों तक रख-रखाव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
44. पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनपीटी) और किसी भी अन्य न्यायालय के आदेश/निर्णय के अधीन है, सामान्य कारण की तर्क जो लागू हो सकती है, सभी तर्कों का खतरा किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
45. परियोजना प्रस्तावक द्वारा We will comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others before commencing the mining operations. बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
46. परियोजना प्रस्तावक द्वारा We will comply. The State Government shall ensure that mining operations shall not be commenced till the entire compensation levied if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2d

August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others. बाबातु रायप पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

47. परिपोजना प्रस्तावक द्वारा "We will Comply the mitigation measures provided in MOEF&CC OM No. Z- 11013/57/2014-IA,II(M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activities on Habitations- Issues related to the mining projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area." बाबातु रायप पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
48. परिपोजना प्रस्तावक द्वारा "We will Comply, we inform to MOEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred. Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the para 11 of EIA Notification, 2006, as amended from time to time." बाबातु रायप पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
49. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य को मॉनिटरिंग एवं सर्वेक्षण हेतु वि-पक्षीय समिति (जोनटाईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित वि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. कार्यालय क्लस्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1146/खनि. सि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 28/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 41.488 हेक्टेयर है। साथ ही उक्त जारी पत्र अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य 2 खदानों को आश्रय पत्र जारी किया गया है, जिसका क्षेत्रफल 4.92 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बुनकट्टा) का क्षेत्रफल 1.86 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बुनकट्टा) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 48.288 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/समाहित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की बानी गयी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की जलखनन शक्तियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों को रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुए, क्लस्टर हेतु कॉम्पन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित करने हेतु संघालय, संघालनालय, भौतिकी तथा खनिज, इंदरावती भवन, नया रामपुर अटल नगर, जिला - रामपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
3. नार्दन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जेन में किये गये प्रावधान हेतु जॉब बन दोषी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु संघालय, संघालनालय,

भौमिकी तथा खनिकर्ण, इटावटी मकन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

4. प्रतिबन्धित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर चौध उपरोक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्ण एवं पर्यावरण को शक्ति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
5. उक्त उत्खनित क्षेत्र (प्रतिबन्धित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी) के पुनर्भरण हेतु ऐस्टीमेशन प्लान को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त अनुमोदा की जाती है।
6. समिति द्वारा विचार किया उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मैसर्स चुनकट्टा लाईन स्टोन माईन (प्री- वी विकास अग्रवाल) को ग्राम-चुनकट्टा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग के पार्ट ब्लॉक क्रमांक 49, 50, 51, 52 एवं 53/1 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.86 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता-19,950 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-03 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमोदा की गई।

राज्य सार्वजनिक पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रियकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

11. मैसर्स चुनकट्टा लाईन स्टोन माईन (प्री- वी विकास अग्रवाल), ग्राम-चुनकट्टा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नक्सी क्रमांक 1851)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 69883/2021, दिनांक 18/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/एमआईएन/432373/2023, दिनांक 08/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-चुनकट्टा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 37(पार्ट), 39(पार्ट), 42(पार्ट), 43(पार्ट), 44(पार्ट), 45(पार्ट), 46(पार्ट), 47(पार्ट), 48(पार्ट), 49(पार्ट), 50(पार्ट) एवं 51(पार्ट), कुल क्षेत्रफल-3.08 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-56,200 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 29/04/2022 द्वारा उपर्युक्त वी1 कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैम्पड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम्.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिलेग्येरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित सेक्शन 1(ए) का स्टैम्पड टीओआर (लोक सुन्वाई सहित) जारी किया गया है।

तदनुसार परिपोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विकास अग्रवाल, प्रोपसाईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेमर्स की एक एम सीएलयुआन, नई दिल्ली, उत्तराखण्ड की ओर से श्री सुभाष कुमार उपस्थित हुए। उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनुमति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत चुनकटा का दिनांक 01/10/2021 को प्रस्ताव पारित किया गया एवं दिनांक 10/10/2021 का अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना — क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भूमिहीन तथा खनिज, नया रायपुर अटल नगर के डायन क्रमांक 4818/खनि 02/न.प्र.अनुमोदन/न.क्र.08/2020(2) नया रायपुर दिनांक 08/09/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के डायन क्रमांक 1148/खनि.सि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 28/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 29 खदानें, क्षेत्रफल 41.488 हेक्टेयर है। साथ ही उक्त जारी पत्र अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य 2 खदान हेतु नवीन अंश पत्र जारी किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3.7 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के डायन क्रमांक 1148/खनि.सि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 28/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनोकेट, राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल लाईन एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण — एल.ओ.आई. श्री विकास अग्रवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के डायन क्रमांक 185/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 22/08/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक वैध थी। तदुपरोक्त एल.ओ. आई. की वैधता कृषि बाबा न्यायालय संचालक, भूमिहीन तथा खनिज, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 80/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 08/11/2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए, यह निर्दिष्ट किया जाता है कि भारतीय न्याय मंत्रालय, 2018 के नियम 42(5) परन्तु के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त सामग्री प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला दुर्ग को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।
7. गू-सामग्री — गूनि पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 37, 44 एवं 48 श्री अमिता कुमार तथा श्री अम्बर कुमार, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 38, 43 एवं 47 श्रीमती नीर, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 42 एवं 48 श्री मोला शंकर अग्रवाल, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 45 श्रीमती मोहनी देवी निभा, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 50 श्री तुलसी

राम मिश्रा, चार्टर्ड ऑफ़ लैंडिंग इन्फार्मेशन 51 श्री राम्भु प्रयाग मिश्रा के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनसम्पदासिक्तारी दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के आपन क्रमांक/सक.अधि./2020/4818 दुर्ग, दिनांक 19/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 60 कि.मी की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी घास-भुनकटा 250 मीटर स्थूल घास-भुनकटा 250 मीटर एवं अस्पताल सेलूड 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 900 मीटर दूर है। तालाब 210 मीटर, खारन नदी 19 कि.मी. दूर है।
11. परिसंस्थितिकीय/जीवविकिण्ण संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोइन्टुटेड एरिया, परिसंस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविकिण्ण क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – गियोलॉजिकल रिजर्व 15,25,772 टन, माइनिंग रिजर्व 8,01,822 टन एवं रिक्वायर्ड रिजर्व 5,41,840 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,966 वर्गमीटर है। आपन कास्ट सेमी कंसेन्ट्रैटेड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं माच 5,344 घनमीटर है, जिसमें से 2,042 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में सीलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा, 852 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को हरित पट्टी से उत्खनित भाग के पुनः मत्तव में उपयोग किया जाएगा एवं शेष 2,390 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 0.870 वर्गमीटर गैर माइनिंग क्षेत्र में संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्वार स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लॉस्टिंग किया जाएगा। खदान में कचरा प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का डिफ्लोव किया जाएगा, बर्बर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	54,970
द्वितीय	96,280
तृतीय	96,280
चतुर्थ	96,280
पंचम	96,280

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरेवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत सैन्ट्रल चार्लक वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,113 वर्ग मीटर वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
खदान की सीमापट्टी में (1,113 वर्ग मीटर) वृक्षारोपण हेतु					
वृक्षारोपण हेतु राशि	84,588	8,436	8,436	8,436	8,436
फेंसिंग हेतु राशि	2,22,900	—	—	—	—
खाद हेतु राशि	8,400	840	840	840	840
सिंचाई हेतु राशि	1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000
रक-रखाव हेतु राशि	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000
कुल राशि = 14,32,964	5,31,888	2,26,276	2,26,276	2,26,276	2,26,276

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 5,588 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 476 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख क्वारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। समिति का मत है कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अतिरिक्त उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

साथ ही समिति का यह भी मत है कि उक्त उत्खनित क्षेत्र (प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी) के पुनर्भरण हेतु रिस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नील कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें क्रमिक 13(a) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार नई लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. गैर माईनिंग क्षेत्र – लीज क्षेत्र में 8,534 वर्गमीटर क्षेत्र को आच्छादी क्षेत्र होने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है।

18. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य मार्च 2022 से मई 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिक्षेत्रीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर सू-जल गुणवत्ता मापन, 8

स्थानी पर ध्वनि स्तर सामान्य, 2 स्थलों पर साहसी जल गुणवत्ता तथा 8 स्थलों पर मिट्टी के नमूने एकांकित का विश्लेषण किया गया है।

ii. सीमितरिग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का मानक लेवल—

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM ₁₀	26.28	43.58	60
PM _{2.5}	47.2	66.5	100
SO ₂	9.08	14.63	60
NO ₂	11.53	20.24	60

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता— ईआईए के Chapter Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार वर्तमान, न्यूट्रेट्स, सल्फर कार्बोनेट्स, लोड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का मानक लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	49.54	61.23	75
Night L _{eq}	40.07	52.41	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू की गणना— भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हवी वाहनों को समाहित करते हुए ट्रेफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 1,830 पी.सी.यू प्रतिघंटा एवं बी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.122 है। प्रस्तावित परियोजना उपरान्त 192 पी.सी.यू की वृद्धि होगी। तात्पर्यतः कुल 2,022 पी.सी.यू प्रतिघंटा एवं बी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.14 होगी। विस्तार के उपरान्त भी सी-मॉटरियल/प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

19. लोक सुनवाई दिनांक 11/01/2023, उपरान्त 12:00 बजे, स्थान - आदिवासी सामुदायिक भवन, ग्राम-मुनकट्टा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सार्वजन्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 18/03/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।

20. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं—

- अदान से बस्ती लगा हुआ है एवं बस्ती का आगनबाड़ी कुछ दूरी पर है।
- अदानों से अस्ट सन्सर्जन होख है।
- अदान से बस्ती लग होने के कारण स्टारिडिंग से अत्यधिक परेशानी होती है।
- स्थानीय लोगों को संज्ञान में प्राथमिकता देना चाहिए।

लोक चुनवाई के दौरान चयन गये विभिन्न भुदों के निराकरण की विस्तार में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- a. लीज के पास जो आगनबाड़ी है, पत्र संकथत जैसे ही जमीन देगी खदान के चालू होने के पूर्व इन आगनबाड़ी के लिए नये विस्डिन का निर्माण करायेगे।
 - b. इस्ट एरसर्जन के नियंत्रण हेतु लीज क्षेत्र की घाटी और प्रथम वर्ष में ही फेशियल कन्ट्रोल प्रशासन किया जायगा। साथ ही कच्ची सड़क पर जल सिंचकाय किया जायगा।
 - c. स्लान्टिंग का कार्य अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक द्वारा निम्न स्तर पर दिन में एक बार की जाएगी। साथ ही स्लान्टिंग के पूर्व इस्टर द्वारा सुचित किया जायगा।
 - d. खदान में काम करने के लिए स्थानीय रहवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
21. कलस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अनेकित खदान को शामिल करते हुये कलस्टर में कुल 28 खदानें जाती हैं। अतः कलस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के सन्दर्भ निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
पूँव मार्ग (10 कि.मी.) के दोनों तरफ (6.687 नम) प्रशासन हेतु	पूँव मार्ग (10 प्रतिफल जीवन दर) हेतु राशि	5,00,000	50,010	50,010	50,010	50,010
	टी-गार्ड हेतु राशि	81,33,800	-	-	-	-
	खार हेतु राशि	50,010	5,010	5,010	5,010	5,010
	सिंचाई हेतु राशि	12,00,000	12,00,000	12,00,000	12,00,000	12,00,000
	सड़-सड़ाव हेतु राशि	9,60,000	9,60,000	9,60,000	9,60,000	9,60,000
कुल राशि = 1,77,12,800		88,50,300	22,15,620	22,15,620	22,15,620	22,15,620

22. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के अंतर्गत प्रस्तुत प्रशासन की गणना में हुई है। अतः समिति का मत है कि कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के अंतर्गत प्रस्तुत प्रशासन की गणना में हुई सुधार कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

[Handwritten Signature]

23. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
65	2%	1.32	Following activities at nearby, Village-Chunkatta	
			Pavitra Van Niman	12.19
			Total	12.19

24. सीईआर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (गैम, आम, केरज, कदम, जामुन, आमला, जमलकास, बड़, पीपल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 228 नए पौधों के लिए राशि 17,176 रुपये, फसिंग के लिए राशि 1,02,800 रुपये, खाद के लिए राशि 1,710 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,28,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,47,686 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,71,712 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत चुनकट्टा द्वारा भी विकास अडवाला, कुल लीज क्षेत्रफल-3.08 हेक्टेयर एवं भी विकास अडवाला, कुल लीज क्षेत्रफल-1.88 हेक्टेयर को सीईआर. के अंतर्गत समुदाय पवित्र वन निर्माण हेतु खासतः प्रत्येक 404 के क्षेत्रफल 0.31 हेक्टेयर में सहभागी प्रदान की गई है।
25. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
26. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान को तहत किये जाने वाले कार्य हेतु अनुबंध करवाकर जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
27. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अज्ञात एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनःसंशोधित कर प्रस्तुत किया गया है।
28. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह एक नवीन खदान है, जो पूर्व से ही चल्थनित है। इस संबंध में समिति का मत है कि उक्त चल्थनित क्षेत्र (प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी) के पुनःनयन हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
29. लीकजुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त उपवासन पुरे किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. घरटीसाहब आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के तहत तक की गई राशि का उपयोग पर्यावरण को हिल में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में जैविक कटाव वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले वृक्षारोपण तथा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यों की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफस सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित किये जाने वाले प्रस्तुत किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
33. एक्सप्लोसिव का कार्य सी.जी.एन.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
34. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःप्राप्त में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
35. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सभ्य वृक्षारोपण किये जाने एवं रक्षित पौधों का सुरुविवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिलेखना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
39. भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन समाप्त से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
40. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल कुएँ, झील, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
41. फ्यूजिंटिव इस्ट उरसर्जन को नियंत्रण हेतु नियमित जल विश्लेषण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
42. आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही वृक्ष वृक्षों की आवश्यकता करने पर ही कटाई रखन प्राधिकारी से अनुमति उपरान्त ही किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
43. सी.ई.आर. की अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 05 वर्षों तक रख-रखाव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।



44. पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और किसी भी अन्य न्यायालय के आदेश/निर्णय के अधीन है, सामान्य कारण की शर्तों जो लागू हो सकती हैं, सभी शर्तों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
45. We will comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others before commencing the mining operations.
46. We will comply. The State Government shall ensure that mining operations shall not be commenced till the entire compensation levied if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2d August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others.
47. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "We will Comply the mitigation measures provided in MOEF&CC OM No. Z- 11013/57/2014-IA.3(M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activities on Habitations- Issues related to the mining projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area." बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
48. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "We will Comply, we inform to MOEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred, Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the para 11 of EIA Notification, 2006, as amended from time to time." बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
49. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कचया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- कार्बलम कलेक्टर (खनिज शायदा), जिला-दुर्ग के ज्ञान क्रमांक 1148/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 28/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 25 खदानें, क्षेत्रफल 41.488 हेक्टेयर है। साथ ही उक्त जारी पत्र अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य 3 खदानें हेतु नवीन आराम पत्र जारी किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3.7 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-धुनकट्टा) का क्षेत्रफल 3.08 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-धुनकट्टा) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 48.268 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (एन.डी.ओ.सी.) के प्रकथनों एवं माननीय एन.डी.ओ.सी. द्वारा जारी आदेशों के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय प्रदूषण पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करती हूँ, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायसमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित किये हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिहीन तथा खनिकर्मा, इंद्रावती मयन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।
3. माईन सीज क्षेत्र के घाटी और 7.5 मीटर चौड़े सेकटी जोन में किये गये उत्खनन हेतु जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिहीन तथा खनिकर्मा, इंद्रावती मयन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जाँच उपरोक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिहीन तथा खनिकर्मा एवं पर्यावरण की शक्ति पशुधाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
5. उक्त उत्खनित क्षेत्र (प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी) के पुनर्स्थापन हेतु सेक्टरियल प्लान को एन.डी.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अर्थात् पर्यावरणीय स्वीकृति की सख्त अनुमति की जाती है।
6. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स बुनकट्टा लाईन स्टोन माईन (प्रो.- श्री विकास अहवाल) को ग्राम-बुनकट्टा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग के खसरा क्रमांक 37(पाटी), 38(पाटी), 42(पाटी), 43(पाटी), 44(पाटी), 45(पाटी), 46(पाटी), 47(पाटी), 48(पाटी), 49(पाटी), 50(पाटी) एवं 51(पाटी) में स्थित चूना पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-3.08 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता-58,250 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-04 में वर्णित शर्तों के अर्थात् पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एन.डी.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स बलुवाबहार सेण्ड स्वीरी (सचिव/सहाय, ग्राम पंचायत अमबीहा), ग्राम-बलुवाबहार, तहसील-करसाबहार, जिला-जरापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2008)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एन.डी.आई.ए.ए./ सीजी/ एम.आई.ए.ए./ 432784/2023, दिनांक 09/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (ग्रीन खनिज) है। यह खदान ग्राम-बलुवाबहार, तहसील-करसाबहार, जिला-जरापुर स्थित खसरा क्रमांक 1, कुल क्षेत्रफल-18.88 हेक्टेयर में से 2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन ईब नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 03/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती अमृता बड़ा, सचिव, ग्राम पंचायत अमरीहा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अमरीहा का दिनांक 25/02/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विन्दकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्दकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-रायगढ़ के पृ. आपन क्रमांक 535/ख.नि. 2/च.पौ./2023 रायगढ़, दिनांक 24/05/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला-जसपुर के आपन क्रमांक 139/खनि.शा./2023 जसपुर, दिनांक 31/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला-जसपुर के आपन क्रमांक 139/खनि.शा./2023 जसपुर, दिनांक 31/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट एवं एंकीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. सचिव/संरपंच ग्राम पंचायत अमरीहा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जसपुर के ज्ञान क्रमांक 38/मी.प खनिज/2023 जसपुर, दिनांक 24/04/2023 द्वारा जारी की गई, जो जारी दिनांक से 01 वर्ष की अवधि हेतु वैध है।

छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, बहलमही मकान, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा छत्तीसगढ़ नीम खनिज साधन रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 हेतु संशोधन अधिसूचना दिनांक 09/08/2023 की जारी की गई है। उक्त अधिसूचना के नियम 4 अनुसार "उत्खनन पट्टे की कारावधि-सम्भारण रेत के उत्खनन हेतु उत्खनन पट्टा पांच वर्ष की कालावधि के लिए प्रदान किया जाएगा। पांच वर्ष की अवधि की गणना उत्खनन पट्टा विलेख के पंजीयन दिनांक से किया जाएगा।" का उल्लेख है।

8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलधिकारी, जसपुर वनमण्डल, जिला-जसपुर के आपन क्रमांक/वा.वि./2021/4530, जसपुर दिनांक 15/11/2021 से जारी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवादी ग्राम-बलुयाबाहार 1 कि.मी. स्कूल एवं अस्पताल ग्राम-लकन 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 कि.मी. राजमार्ग 17 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेल खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनिकट स्थित नहीं है।
11. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 237 मीटर, न्यूनतम 218 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई - अधिकतम 270 मीटर, न्यूनतम 260 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 84 मीटर, न्यूनतम 68 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 114.1 मीटर, न्यूनतम 28.5 मीटर है।
12. खदान स्थल पर रेत की गौराई - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई - 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनिंग रेत की मात्रा-40,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की गौराई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.05 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।
13. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के चिह्न बिन्दुओं पर दिनांक 19/08/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, सभी खनिज विभाग से प्रामाणिकरण अनुरोध फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से पर्यावरण निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
20	2%	8.40	Following activities at Govt. Primary School, Village - Baluwabahaar	
			Plantation	5.38
			Total	5.38

15. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण के उद्देश्य (ग्रीन जाम, महुआ आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 20 भाग पीछी के लिए राशि 2,400 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 35,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रक-रखाव आदि के लिए राशि 82,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष

में कुल राशि 1,37,450 रुपये तथा अगामी 4 वर्षों में कुल राशि 4,00,980 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहजीव पत्र प्रस्तुत किया गया है।
17. वृक्षारोपण कार्य - नदी तट एवं पहुंच मार्ग में 800 नम वृक्षारोपण करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है, जो निम्नानुसार है:-

विवरण		प्रथम वर्ष (रुपये)	द्वितीय वर्ष (रुपये)	तृतीय वर्ष (रुपये)	चतुर्थ वर्ष (रुपये)	पंचम वर्ष (रुपये)
नदी तट एवं पहुंच मार्ग में (800 नम) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन वृक्ष) हेतु राशि	28,000	2,800	2,800	2,800	2,800
	फसिल हेतु राशि	1,45,000	-	-	-	-
	खाद हेतु राशि	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	शिफ्ट एवं रख-रखाव हेतु राशि	1,84,500	1,84,500	1,84,500	1,84,500	1,84,500
कुल राशि = 11,28,700		3,61,500	1,91,300	1,91,300	1,91,300	1,91,300

18. पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत जो भी राशि लग करे जाएगी उसका उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) के तहत निर्धारित राशि का उपयोग दिये गये कार्य में ही किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. न्यूजिटिव इस्ट एसाजमेंट के नियंत्रण हेतु निर्धारित जल छिड़काव किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, जन जीव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रस्तावना का प्रकरण लंबित नहीं है।
24. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ओवरसाइट/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं

नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

25. लीज क्षेत्र के चारों कोनों तथा सीमा लाईन के कवच में बीमेट को खम्बे लगाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
26. रेत उत्खनन मैन्युअल विधि से एवं भराई का कार्य लीडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लीडर जैसे बड़ा भारी वाहन की बेनी के है। अतः भराई का कार्य मैन्युअल विधि से ही कराई जाये। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति नहीं है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। ईश नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षोत्तर में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. अनेदिता खदान (घाम-बलुवाबहार) का रकबा 2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान की-2 बेनी की मानी गयी।
2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत ग्राउंड अध्ययन (Situation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबर सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के मानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
3. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाइन डाटा —
 - i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित छिद्र बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छातीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।
 - ii. पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं छिद्र बिन्दुओं में माइनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अवरस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक लंबा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित छिद्र बिन्दुओं पर किया जायेगा।
 - iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरान्त मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं छिद्र बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
 - iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित छिद्र बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छातीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से मेसर्स बलुवाबहार सोल्ड क्वीरी (संधिव/सरपंच, घाम पंचायत अमकीहा), खरवा क्रमांक 1, घाम-बलुवाबहार

तहसील-कनसाबहार, जिला-बनारस, कुल लीज क्षेत्रफल 2 हेक्टर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 12,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु पर्सिस्टेंट-06 में वर्णित शर्तों के अधीन दिखे जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में नारी गाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्लॉट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सैंड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
6. इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सैंड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) की उद्दा 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सुधारा किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-3:

परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वर्णित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्देश लिया जाना।

1. मेसर्स शिवाय इन्फ्रा (पार्टनर- श्री राजेश कुकरेजा), ग्राम-लामाण्डी, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय का नसी क्रमांक 2344)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नंबर - एसआईए/ सीजी/ इन्फ्रा2/423087/ 2023, दिनांक 29/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-लामाण्डी, तहसील व जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 16002 (109/3, 109/7, 109/1, 109/10, 109/18, 109/27, 109/29, 109/30, 109/48, 109/53), कुल क्षेत्रफल-1.27 हेक्टर, कुल विल्टजन एरिया 28,589.8 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 52 करोड़ होगी।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुधारा किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 461वीं बैठक दिनांक 28/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुकरेजा, पार्टनर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स की एण्ड एन सॉल्यूशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री हरीन जगतवर्दीन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. निकटतम विद्या क्रियाकलापों संबंधी जानकारी -

1. निकटतम आबादी नावना नगर 340 मीटर, राखपुर रेलवे स्टेशन 5.2 किमी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, राखपुर 8.48 किमी., अस्पताल 4.18 किमी. एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 1.38 किमी. दूर है। तेलीबाधा तालाब 2.31 किमी. एवं खासन नदी 9.53 किमी. दूर है।
2. परियोजना प्रसन्नक द्वारा 10 किमी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्ताराष्ट्रीय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित डिस्टिक्यूटी पील्लुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविकिषल क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
3. सञ्जुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, राखपुर के ज्ञापन क्रमांक 9769/नयानि/घरा-29/CGAWAAS/2021/00048/2021 राखपुर, दिनांक 22/07/2021 अनुसार विकास अनुज्ञा जारी की गई है।
4. कार्यालय नगर पालिक निगम, राखपुर के ज्ञापन दिनांक 16/12/2021 द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत की गई है।
5. छात्रीसमूह रिजल एग्जेट विधायक प्राधिकरण के ज्ञापन दिनांक 01/01/2022 द्वारा फंजीशन प्रमाण पत्र जारी की गई है, जिसकी किता 04/10/2028 तक है।
6. भू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 15,002 मेसर्स शिवाच इन्डा (घार्टनर-श्री शकेश कुकरेजा), श्रीमती राखी कुकरेजा, श्रीमती कला शर्मा एवं मेसर्स वी3 विल्डबॉन प्रा.लि. (डीपरेक्टर- श्री विकास धारख) के नाम पर है।
7. लेम्ब चुरिया स्टेटमेंट -

S. No.	Particulars	Area (m ²)	Area (%)
1.	Proposed Ground Coverage	2,513	19.78
2.	Green Area	4,191	33.00
3.	Road / Paved Area	1,450	11.42
4.	Open Area	4,546	35.80
Total Area		12,700	100

7. विल्टअप चुरिया स्टेटमेंट - प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रसन्नक द्वारा बताया गया कि कुल विल्टअप चुरिया 28,589.8 वर्गमीटर है। समिति का मत है कि उस अनुसार (Floor wise) विल्टअप चुरिया की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. प्रस्तावित कार्यकलापों की सुविधाओं के उपयोग हेतु अनुमानित कुल 505 व्यक्तियों द्वारा किया जाना बताया गया है।
9. वायु प्रदूषण नियंत्रण - निर्माण के दौरान उत्पन्न फ्युजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढक कर निर्माण कार्य किया जाएगा एवं नियमित जल छिड़काव किया जाएगा।
10. शीश अपशिष्ट प्रबंधन - निर्माण के दौरान उत्पन्न मिट्टी को ढके हुए क्षेत्र में रखा जाएगा एवं उस मिट्टी का उपयोग लेम्ब स्टैपिंग, लेवलिग एवं डेक डिलिंग में उपयोग किया जाएगा। रिसाईसलेबल अपशिष्टों (ड्रोकन ब्रिक्का, ड्रोकन टाईल्स, लकड़ी के टुकड़े, सीमेंट बैग्स आदि) को अधिकृत वेण्डर्स को विक्रय किया जाएगा तथा शीश रिजेक्ट मटेरियल को अर.एन.सी. द्वारा बताने वाले स्थल

पर उपग्रहण किया जाएगा। पार्श्व स्वतः पर समिती द्वारा उत्पन्न अपशिष्टों को दैनिक आधार पर स्थानीय एजेंसियों द्वारा अन्वहण किया जाएगा।

परियोजना के विकसोपयुक्त डोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु धी तिन पद्धति अपनायी जाएगी। परियोजना से उत्पन्न कुल डोस अपशिष्ट की मात्रा 425.8 किलोग्राम प्रतिदिन (रिसीवेल्स द्वारा 237 किलोग्राम प्रतिदिन तथा कन्सिपल, स्टाफ एवं विजिटर्स द्वारा 188.9 किलोग्राम प्रतिदिन) होगी। उत्पन्न डोस अपशिष्टों को वेद एवं रिसाईक्लेबल के अनुसार संग्रहित किया जाएगा। रिसाईक्लेबल अपशिष्टों को अधिकृत वेपर्स को विक्रय किया जाएगा।

11. जल प्रबंधन व्यवस्था -

- जल सपल एवं स्रोत - परियोजना में ऑपरेशन फेज हेतु 140.98 घनमीटर प्रतिदिन (फेश वॉटर हेतु 108.23 घनमीटर प्रतिदिन एवं पलशिंग हेतु 32.75 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति नगर निगम द्वारा की जाएगी। परियोजना में कन्स्ट्रक्शन फेज हेतु जल की आपूर्ति मू-जल के माध्यम से किया जाना बहया गया है। समिति का मत है कि जल की आपूर्ति नगर निगम से किये जाने बहय सहमति पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- जल प्रदूषण नियंत्रण - उत्पन्न दूषित जल की मात्रा 118.73 घनमीटर प्रतिदिन होगा। दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 126 घनमीटर प्रतिदिन स्थापित किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, इफ्लेलाइजेशन टैंक, एमबीबी रिएक्टर, सेप्टिक टैंक, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, सलज होल्डिंग टैंक एवं ड्रेसर सेप्टिक फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल को डिसइन्फेक्शन कर पुनारोपण हेतु उपयोग किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उत्पन्न सलज का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाएगा।

- मू-जल उपयोग प्रबंधन - परियोजना स्थल सेंट्रल घासख घाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जीन में आता है। जिसके अनुसार-

(अ) वृद्ध एवं मध्यम उम्रों की कम से कम 60 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) घासख घाटर रिचार्ज हेतु अनाई नई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर मू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल घासख घाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्राधान्य है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- रेन वाटर हार्वेस्टिंग - परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 4,885.71 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 3 नग रिचार्ज पिट (ज्यास 1.9 मीटर एवं गहराई 4 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पर्याप्त परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

12. विद्युत सपल - परियोजना हेतु 1500 किलोवॉट की आवश्यकता होगी। विद्युत आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा।

वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 4 नग (2x500 एवं 1x125) की.जी.सी. सीट स्थापित किये जाएंगे। समिति का मत है कि की.जी.सी. सीट से संतन्न विमनी की ऊंचाई की गणना कर जानाकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. वृक्षारोपण संबंधी विवरण - हरित पट्टिका के विस्तार हेतु 4.124 वर्गमीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना बताया गया है। परिसर के चारों ओर 1,040 नग (मध्यम ऊंचाई वाले) एवं आंतरिक मार्गों के किनारे 1,040 नग (कम ऊंचाई वाले) वृक्षारोपण किया जाएगा। इस प्रकार परिसर के भीतर कुल 2,080 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि परिसर के भीतर वृक्षारोपण हेतु पीछों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुखा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. ऊर्जा संरक्षण उपकरण - आंतरिक स्थानों पर एल.ई.डी. लाइट प्रयुक्त किया जाना प्रस्तावित है। लैम्प स्वीचिंग एवं ड्राईव-वे में स्कोलर एल.ई.डी. लाइटिंग सिस्टम लगाना जाना प्रस्तावित है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत कुल लागत का 1.5 प्रतिशत व्यय किया जाना बताया गया। जबकि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार 100 करोड़ तक के तीन बिल्ड प्रोजेक्ट हेतु 2 प्रतिशत सहित सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु व्यय किया जाना है। समिति का मत है कि कुल प्रस्तावित लागत के 2 प्रतिशत सहित अनुसार परियोजना के अलग-थलग सहमति प्राप्त सासादीय भूमि (अथवा प्रभाव एवं क्षेत्रफल सहित) में ईको पार्क निर्माण के तहत विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा वृक्षारोपण हेतु पीछों का रोपण, सुखा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार नगर निगम से अनुमति प्राप्त प्रमाण पत्र /सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्कालीन सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. श्री किशन सिंह धुब, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं डॉ. मनोज कुमार घोषकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तीरगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को सम्मिलित करते हुए तीन सदस्यीय उपसमिति का गठन किया जाते है। तीन सदस्यीय उपसमिति स्थल का निरीक्षण करेगी तथा अद्यतन स्थिति से अद्यतन कराते हुए कलरमुक्त फोटोग्राफ्स दिनांक सहित विन्दुवार निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
2. तल अनुसार (Floor plan) बिल्टअप एरिया की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. जल की आपूर्ति नगर निगम से किये जाने बाबत सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. की.जी.सी. सीट से संतन्न विमनी की ऊंचाई की गणना कर जानाकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. परिसर के भीतर वृक्षारोपण हेतु पीछों का रोपण (न्यूनतम 90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुखा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

1. परियोजना के संक्षेप में भूमि संबंधी विवरण :-

- मेराई सिविल इन्फ्रा (प्राइवेट)- श्री राजेश कुकरेजा, ग्राम-ताभाम्डी, तालुका व जिला - रायपुर (छ.ग.) का खसरा क्रमांक - 15002 (108/3, 108/7, 109/1, 109/10, 109/18, 109/27, 109/29, 109/30, 109/48, 109/53), कुल रकबा 1.27 हेक्टर के संक्षेप में उपर संचालक कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा 4 ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) द्वारा विज्ञापन अनुक्रमांक पत्र क्रमांक 9769/ नगरनि/ पाठ-28/ CGAWAAS/2021/00048/2021 दिनांक 22/07/2021 को प्रदत्त किया गया है। उक्त बाबत भौके पर उपस्थित परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 30/06/2023 को वी गई जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
- उपरोक्त परियोजना हेतु कार्यालय, नगर पालिक निगम रायपुर (छ.ग.) जॉन क्रमांक-9 द्वारा प्रकरण संवीक्षण क्रमांक [29098], (VSNA-RMC-2021-0008) दिनांक - [24.11.2021], अनुक्रमांक - 102247, दिनांक 18/12/2021 के माध्यम से उपरोक्त परियोजना के संक्षेप में भवन निर्माण अनुक्रमांक जारी की गई है। उक्त बाबत भौके पर उपस्थित परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 30/06/2023 को वी गई जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
- खेतीबाड़ी के विकास की अंतिम (PROVISIONAL) अनुमति जिसमें संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत अभिन्यास के अनुसार कुल भूमि रकबा 12,700 वर्गमीटर में से मार्ग अंतर्गत एरिया - 730.18 वर्गमीटर छोड़कर नेट स्वैम एरिया 11,969.81 वर्गमीटर पर टोटल बिल्टअप एरिया 26,999.8 वर्गमीटर (टोटल रेसिडेन्शियल फ्लैट बिल्टअप एरिया 24,289.80 वर्गमीटर, कामर्शियल क्लब एरिया 1.428 वर्गमीटर एवं कामर्शियल शॉपिंग एरिया 808 वर्गमीटर सहित) अनुमोदित होने का उल्लेख किया गया है। उक्त बाबत भौके पर उपस्थित परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 30/06/2023 को वी गई जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
- निरीक्षण के समय पाई गई स्थिति के अनुसार परियोजना स्थल में कारपट्टी बाल निर्मित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना स्थल पर निर्माण कार्य नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उनके पत्र दिनांक 07/07/2023 के माध्यम से उपरोक्त परियोजना के संक्षेप में ग्राम ताभाम्डी पत्र.नं. - 65 दिनांक 06/07/2023 के खसरा नक्शा की प्रति प्रेषित की गई है, जिसमें प्रस्तावित खुली भूमि खसरा क्रमांक 15002 (108/3, 108/7, 109/1, 109/10, 109/18, 109/27, 109/28, 109/30, 109/48, 109/53), कुल रकबा 1.27 हेक्टर का उल्लेख है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा अभिलेखीकृति प्रस्तुत की गई है, जिसमें उपरोक्त खसरों का उल्लेख करते हुए ग्राम ताभाम्डी, रायपुर छ.ग. कुल रकबा 12,700 वर्गमीटर पर कुल निर्माण क्षेत्रफल 26,944 वर्गमीटर प्रस्तावित होने का उल्लेख किया गया है।
- भौके पर लिये गये फोटोग्राफ्स की प्रति प्रस्तुत किये गये हैं।

2. जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था- परियोजना से जनित होने वाले घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु परियोजना द्वारा 120 के.एल.डी. क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है। उपचारित घरेलू दूषित जल का उपयोग वृक्षारोपण की सिंचाई आदि में किया जाना प्रस्तावित है। उक्त बाबत

मीके पर उपस्थित परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 30/08/2023 को दी गई जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

3. कुआरोपन के संबंध में जानकारी— परियोजना द्वारा निम्नानुसार कुआरोपन किया जाना प्रस्तावित है।
 4. दोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था— परियोजना द्वारा जमित होने वाले दोस अपशिष्टों को पृथक-पृथक बिनस में एकत्र कर नगर पालिक निगम को हटाव किया जाना प्रस्तावित है।
 5. सी.ई.आर. के संबंध में जानकारी— परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के संबंध में कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।
2. तल अनुसार (Floor wise) बिल्टअप एरिया निम्नानुसार है—

Details of Towers	Area (m ²)
Tower-1	4,320
Tower-2	4,320
Tower-3	4,320
Tower-4	4,320
Tower-5	4,320
Tower-6	4,091 (1,428 Comm. + 2,663 resl.)
Shops Comm.	908
Total Area	28,599

3. जल की आपूर्ति नगर निगम से किये जाने बाबत अनुमति कन्स्ट्रक्शन के उपरांत ही ली जाएगी। वर्तमान में टैंकर तथा भू-जल के माध्यम से ही कन्स्ट्रक्शन का कार्य किया जाएगा। इस बाबत रोन्टल साइमन्स वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
4. सी.पी. रोड से संलग्न चिन्नी की ऊंचाई बिल्डिंग की ऊंचाई 36 मीटर से 3 मीटर अधिक (इस प्रकार कुल चिन्नी की ऊंचाई 39 मीटर) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है।
5. परिसर के भीतर कुआरोपन हेतु 3,640 मग पीछों के लिए राशि 2,78,840 रुपये, फौजिंग के लिए राशि 87,000 रुपये, खाद के लिए राशि 30,000 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रुपये एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,98,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 7,19,840 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 9,98,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु षट्कवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल प्रस्तावित लागत के 2 प्रतिशत राशि अनुसार सी. ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
5309	2%	104	Following activities at Village- Amethi	

			Pavitra Nirman	111.455
			Total	111.455

7. सी.ई.आर. के अंतर्गत 'स्वच्छ वन निर्माण' के तहत (आंबला, कपूर, नीम, आम, जामुन, कदम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 13,500 नम पैधों के लिए राशि 10,28,000 रुपये, फंसिंग के लिए राशि 2,19,300 रुपये, खाद के लिए राशि 1,01,250 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 8,40,000 रुपये तथा रख-रखाव के लिए राशि 12,76,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 34,82,550 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 78,82,980 रुपये हेतु पाटकदार व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा धाम पंचायत असेंबली के सदस्यता संघर्षत पंचायत स्थान (खसरा क्रमांक 443, क्षेत्रफल 5.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

8. परिवार क्षेत्र के अंदर कुक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पैधों का काम से काम सारवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई चलसंपन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार किया करता सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मेसर्स सिद्ध इन्फ्रा (पार्टनर- श्री राजेश कुम्हरेजा), धाम-ताभापकी, तहसील व जिला-रायपुर में खसरा क्रमांक 15002 (108/3, 108/7, 109/1, 109/10, 109/16, 109/27, 109/29, 109/30, 109/46, 109/53), कुल क्षेत्रफल-1.27 हेक्टेयर, कुल विलक्षण एरिया 28,599.6 वर्गमीटर हेतु परिशिष्ट-08 में वर्णित शर्तों के अंदर पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य सार्वजनिक पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स भुईगांव सैण्ड माईन (प्री- सरपंच, धाम पंचायत बासनवाही (श्री एमेश कुमार नेतान्)), धाम-भुईगांव, तहसील-बारामा, जिला-रायपुर बस्तर कॉर्पोरेशन (सचिवालय का नक्शा क्रमांक 2355)

ऑनलाइन आवेदन - इन्फोर्मल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 422942/2023, दिनांक 29/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत (गोम खनिज) खदान है। खदान धाम-भुईगांव, धाम पंचायत बासनवाही, तहसील-बारामा, जिला-रायपुर बस्तर कॉर्पोरेशन स्थित प्लॉट क्रमांक खसरा क्रमांक 847, कुल क्षेत्रफल-28.88 हेक्टेयर में से 5 हेक्टेयर में

प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेल उत्खनन क्षमता—1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

समानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 03/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 10/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एमेश कुमार नेतान, ससपंच, ग्राम पंचायत बासनवाही उपस्थित हुए। समिति द्वारा नमती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — रेल उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बासनवाही का दिनांक 12/08/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विन्दायित/सीमांकित — खदान विन्दायित/सीमांकित कर घोषित कर कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु खनि अधिकारी, जिला-उत्तर बस्तर कार्केर को कार्यालय, ग्राम पंचायत बासनवाही द्वारा दिनांक 10/09/2022 को आवेदन किया गया है।
4. उत्खनन योजना — जारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (ख.उ.), जिला-उत्तर बस्तर कार्केर के आपन क्रमांक 477/खनिज/उत्ख.पी.अनु./रेल/2022-23 उत्तर बस्तर कार्केर, दिनांक 07/03/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कार्केर के आपन क्रमांक 582/खनिज/ख.लि./रेल/2023 कार्केर, दिनांक 24/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेल खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/राजमार्ग — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कार्केर के आपन क्रमांक 581/खनिज/ख.लि./रेल/2023 कार्केर, दिनांक 24/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, बरघट एवं एनोबट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। गौरव 180 मीटर की दूरी पर स्थित है।
7. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण — एल.ओ.आई. ससपंच, ग्राम पंचायत बासनवाही के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर-कार्केर के आपन क्रमांक 385/खनिज/रेल/2023 कार्केर, दिनांक 24/02/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है। जारी एल.ओ.आई. में "उत्खनन पट्टे विलेक के पंजीयन के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के लिए विधि मान्य होगा।" का उल्लेख है।

16. सीईआर पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के सन्धा विस्तार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
48.5	2%	0.97	Following activities at Nearby Village- Bhuigaon	
			Plantation at government land near by lease area	5.43
			Total	5.43

16. सीईआर के अंतर्गत लीज क्षेत्र के समीप शासकीय भूमि में (बड़, पीपल, नीम, करंज आम, इमली, अर्जुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 600 नग पौधों के लिए राशि 30,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 60,000 रुपये, खाद के लिए राशि 8,000 रुपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 67,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,13,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में रख-रखाव हेतु कुल राशि 3,30,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के सहमति उपरान्त यथादीन्य स्थान (खसरा एवं क्षेत्रफल सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. वृक्षारोपण कार्य – नदी तट पर (बड़, पीपल, नीम, करंज, आम, इमली, अर्जुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 400 नग पौधों के लिए राशि 30,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 60,000 रुपये, खाद के लिए राशि 4,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 68,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,62,000 रुपये प्रथम वर्ष में एवं कुल राशि 3,00,000 रुपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. खदान विन्यासित/सीमांकित कर घोषित कर कार्यालय कलेक्टर, खनिज सारवा से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. सीईआर के अंतर्गत लीज क्षेत्र के समीप शासकीय भूमि में वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत के सहमति उपरान्त यथादीन्य स्थान (खसरा एवं क्षेत्रफल सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र को बाहर उत्खनन कार्य नहीं किये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. पर्यावरण अदालत पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

4. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विस्तृत इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विस्तृत भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.सा. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्खनन का प्रकरण लंबित नहीं है।
7. सी.ई.ओ.ए. कार्य एवं नदी तट में कुशासन कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के प्रमुख/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के महाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.ओ.ए. एवं नदी तट में कुशासन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
8. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लीडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लीडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के हैं। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जाये। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति नहीं है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तात्काली जांचों का समावेश नहीं किया गया है। गहानदी बड़ी नदी है तथा इन्हें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. उपरोक्त खदान (ग्राम-बुईगांव) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान की-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Situation Study) करायेंगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) कायम सही जाँकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंपत्ति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
3. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाइन डाटा —
 1. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के सतरी (Levels) का सर्वे कर, उसके जाँकड़े तालुका एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।
 2. पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवंबर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पुरी) इन्ही विभिन्न बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट

(मोनों और) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के तारी (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विच बिन्दुओं पर किया जाएगा।

- ii. इसी प्रकार रेत खनन उपरत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी विच बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल (Levels) का मापन किया जाएगा।
- iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित विच बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल (Levels) के मापन का कार्य आगामी 8 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। सैट-मानसून के आंकड़े विसाखर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए. प्रतीकण्ड को प्रस्तुत किए जाएंगे।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरत सर्वसम्मति से वेदास भुईगांव रोड बाईन (प्री- सखेय, ग्राम पंचायत बरानवाही (बी एनए कुनार नेताम)), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 847, ग्राम-भुईगांव, ग्राम पंचायत बरानवाही, तहसील-घासना, जिला-उत्तर बरान कांठ, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टर में उत्खनन हेतु रेत क्षेत्र का कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन परदे के निष्पादन की शर्तों से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-8 में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
5. सस्टेनेबल सैण्ड मनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सैण्ड मनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार फालन सुनिश्चित किया जाए।
6. इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सैण्ड मनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 80 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.) प्रतीकण्ड को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. वेदास वासवाणी इन्फ्रस्ट्रक्चर लिमिटेड, ग्राम-सोमवा, तहसील व जिला-रावपुर (सचिवालय का नक्का क्रमांक 1554)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्व में प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/सीजी/आईएनडी /80799/2021, दिनांक 14/02/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/80799/ 2021, दिनांक 01/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई. ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह क्षमता विस्तार का प्रकार है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्य-कलाप के तहत, ग्राम-सोमवा, तहसील व जिला-रावपुर स्थित खसरा

क्रमांक 404, 405/1, 405/2, 406/1, 406/2, 406/3, 406/4, 407/1, 407/2, 409/1, 409/2, 409/3, 410/1, 410/2, 411/1, 411/2, 412, 413, 414, 415, 416/1, 416/4, 416/5, 416/6, 416/7, 417/1, 417/2, 417/3, 417/4, 417/5, 417/6, 418/1, 418/2, 418/3, 418/4, 419, 454/1, 454/2, 455, 459, 463/1, 463/2, 463/3, 463/4, 463/5, 463/6, 463/7, 463/8 एवं 484/1, क्षेत्रफल - 11.84 हेक्टर से 18.6 हेक्टर (45.9 एकड़) में इम्बेल्डमेंट करीब विध एल.आर.एच. से (एम.एस. विलेट, इन्फ्रास्ट्र/ड्रॉट विलेट्स) - 38,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,50,000 टन प्रतिवर्ष, न्यू सेलिंग मिल (ग्रे-टैल्ड प्रोडक्ट/पत्रा/स्ट्रक्चरल स्टील/वायर रॉड) - 1,50,000 टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणमैत्रीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग का कुल लागत 27 करोड़ होगा।

पूर्व में एम.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 645, दिनांक 28/08/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2015 में प्रकाशित स्टैम्पड एम्स ऑफ रिकॉर्ड (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्गित श्रेणी 3(ए) का स्टैम्पड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इन्डस्ट्रीज (फ़ैस एन्ड नॉन फ़ैस) हेतु टीओआर जारी किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 06/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकी का विवरण -

(अ) समिति की 438वीं बैठक दिनांक 06/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 06/12/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अचिरकार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 439वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री वीरमल बालवानी, सीओओ एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पर्यावरण इन्वायरी लेबोरेट्रीज एम्ड कन्सलटेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री वाय. रेड्डी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. जल एवं वायु सम्पत्ति -

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, रायपुर से राज आवसन क्षमता-80,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, डबल्यू.एम.आर.बी. आधारित कंस्ट्रिक्ट पोवर प्लांट-8 मेगावाट, एफ.बी.सी. आधारित कंस्ट्रिक्ट पोवर प्लांट-2.5 मेगावाट एवं एम.एस. इन्फ्रास्ट्र/विलेट्स क्षमता-38,000 मीट्रिक टन

प्रतिबन्ध हेतु जल एवं वायु सम्बन्धी नवीनीकरण दिनांक 08/04/2021 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 31/03/2024 तक वैध है।

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, रायपुर के आपन दिनांक 08/01/2022 द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्बन्धी शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार शर्त क्रमांक 5 का अपूर्ण पालन होता बताया गया है एवं शेष शर्तों का पूर्ण पालन किया जाना बताया गया है। इस संबंध में स्मिति का मत है कि अपूर्ण शर्त का पूर्ण पालन करने के संबंध में कार्यसूचक एवं जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. भूमि मालिकता/भूमि आकंटन संबंधी दस्तावेज खसरादार सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. सामीप्य स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –
- समीपस्थ अलादी घास-सोपड़ा 100 मीटर एवं शहर रायपुर 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम अस्पताल 2.8 कि.मी., स्कूल 2.3 कि.मी. दूर है। निकटतम रेलवे स्टेशन मांडर 7.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानमैदान, माना, रायपुर 22 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है। खालन नदी 2.5 कि.मी., खोखरा नाला 1.2 कि.मी. दूर है।
 - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, सेन्ट्रीक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिवेदित किया है।
4. लैण्ड एरिया स्टेटमेंट – वर्तमान में इकाई 11.84 हेक्टेयर में स्थापित है। अन्धता विस्तार हेतु 8.78 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित की गई है। कुल क्षेत्रफल 18.6 हेक्टेयर (45.9 एकड़) है, जिसमें से बीसाइड ईक्विन (डब्ल्यू.एच.आर.पी.) का क्षेत्रफल 3 एकड़, इन्फ्रस्ट्रक्चर फर्नेस का क्षेत्रफल 2 एकड़, रोलिंग मिल का क्षेत्रफल 2 एकड़, एफ.बी.सी. आधारित पावर प्लांट का क्षेत्रफल 1.5 एकड़, स्टोरेज एरिया 5 एकड़, आंतरिक मार्ग का क्षेत्रफल 3 एकड़, पार्किंग का क्षेत्रफल 1 एकड़, वाटर रिजर्वायर एम्बेड रिन वॉटर हार्डनिंग का क्षेत्रफल 2.5 एकड़, एडमिन बिल्डिंग का क्षेत्रफल 0.05 एकड़, ऑफिस एरिया 7.45 एकड़ तथा इतिरिक्त हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 18.4 एकड़ है।

5. सी-कॉन्टेंट –

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode Of Transport
1	For Steel Melting Shop (MS Billets/ Ingots) – 1,50,000 TPA			
A	Sponge Iron	1,52,000	Own generation & Open market	By road (through covered trucks)
B	MS Scrap / Pig Iron	23,000	Chhattisgarh	By road (through covered trucks)
C	Ferro alloys	3,000	Open market	By road (through covered trucks)
2	For Rolling Mill through Hot charging (Rolled Products) – 1,50,000 TPA			
A	Hot Billets / MS	1,65,000	Own generation &	By road

(Handwritten signature)

	Billets / Ingots		Open market	(through covered trucks)
3	Gasifier for Rolling mill (2,000 Nm ³ /hr)			
A	Coal (Indian)	1,640	SICL, Chhatbisgarh / MCO, Odisha	By rail & road (through covered trucks)
B	Coal (Imported)	1,800	Indonesia / south Africa / Australia	Through sea route, rail route & by road

d. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Unit (product)	Existing Operating Plant	Proposed Expansion project	After Expansion project	
1.	DRI Kline (sponge iron)	80,000 TPA (3 x 100) TPD)	-	80,000 TPA (3 x 100 TPD)	
2.	Induction Furnace (MS Billet / Ingot)	35,000 TPA (2 x 8 T)	1,14,000 TPA (Replacement of 2x8 T with 2x10 T IF & installation of new 2x15MT IF with matching LRF)	1,50,000 TPA (2x10 T & 2x15 T)	
3.	Rolling mill (Re-rolled product/semi-structural steelwire rod)	-	1,50,000 TPA (1 x 500 TPD) [1,27,500 TPA through hot charging & 22,500 TPA through Reheating furnace]	1,50,000 TPA (1 x 500 TPD) [1,27,500 TPA through hot charging & 22,500 TPA through Reheating furnace]	
4.	Power Plant	WHRB	9 MW	-	9 MW
		FBC	2.5 MW	-	2.5 MW

7. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – वर्तमान में इण्डियन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्युम एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं 2 नम 35 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित है। समस्त विस्तार के तहत इण्डियन फर्नेस में प्युम एक्सट्रैक्शन सिस्टम (उपग्रह कर) के साथ बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मीटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। रि-हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्कबर स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप के लिए प्रस्तावित नई व्यवस्था से पार्टिकुलेट मीटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से घटाकर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर होना प्रस्तावित है। रोलिंग मिल में 30 मीटर ऊँची चिमनी प्रस्तावित है। न्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल सिंक्राउट व कचई कन्वेंयर सिस्टम उपयोग किया जाएगा।

8. दोष अपशिष्ट उपबन्धन व्यवस्था –

S. No.	Waste	Capacity (TPA)		Method of disposal
		Existing	Proposed	
1	Ash from DRI	16,000	-	Is being used in two brick manufacturing units operating in plant premises.
2	Dolomite	27,000	-	Is being used as fuel for FBC based power plant.
3	Min Acetation slag	810	-	Is being utilized in road construction & used in two brick manufacturing units operating in plant premises.
4	Wet scraper sludge	4,140	-	Is being utilized in road construction & used in two brick manufacturing units operating in plant premises.

दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सौकरिड निर्माण किया गया है। धरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। गैसीफायर से ज्विता किन्हीनिक दूषित जल को खाद के पुरे से स्थापित स्नैज आयरण किल्ल में अपवहन किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्कारण की स्थिति रखी जाएगी। समिति का मत है कि उत्पन्न औद्योगिक दूषित जल अनुसार इम्प्युएंट ट्रीटमेंट प्लांट एवं धरेलू दूषित जल अनुसार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था हेतु जानकारी (श्रमा, कुर्बांग सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **भू-जल उद्योग प्रबंधन** — उद्योग स्थल सेंट्रल प्राथमिक वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में अला है। जिसके अनुसार—

(अ) कुहर एवं नद्यन उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) प्राथमिक वाटर रिचार्ज हेतु अगनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल प्राथमिक वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** — उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रकबा 3,854 घनमीटर प्रति घण्टा है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 8 नग रिचार्ज पिट (ऊँचा 2 मीटर, गहराई 8 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरोक्त कुल 12 नग रिचार्ज पिट (व्यास 4 मीटर, गहराई 8 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था परचात् परिसर को पूर्ण रकबा की रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएँ कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

10. **विद्युत आपूर्ति स्रोत** — वर्तमान में परियोजना हेतु 10 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता है। संस्था विस्तार उपरोक्त परियोजना हेतु कुल 17 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती जिसमें से 5.5 मेगावॉट विद्युत की आपूर्ति सीएसपीडीसीएल एवं 11.5 मेगावॉट विद्युत की आपूर्ति केंद्रीय पीवर प्लांट से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट की संख्या सहित एवं किन्हीं संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** — वर्तमान में 1.72 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरोक्त हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 16.4 एकड़ (7.45 हेक्टेयर) 40.08 प्रतिशत क्षेत्र में पीछे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों तरफ 20 मीटर की चौड़ी सीमा चट्टी में एवं समीपस्थ गांव की तरफ 40 मीटर की चौड़ी सीमा चट्टी में वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रति हेक्टेयर 2,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि प्रस्तावित उद्योग परिसर के चारों ओर एवं उद्योग क्षेत्र के रिक्त स्थान में भी वृक्षारोपण हेतु 5 से 8 फीट ऊँचाई वाले पीछे का रोपण (50 प्रतिशत जीवन पर सहित), मुखा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रखा-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटककार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव ले-आउट प्लान में दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि 50 प्रतिशत क्षेत्रफल में पीछे रोपित किया जाना आवश्यक है।

12. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण—

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी — मॉनिटरिंग कार्य 01 मार्च, 2021 से 20 जून, 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतराल 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता साम्प, 8 स्थानों पर नू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर साम्प, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ_x का साम्पन लेवल—

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM ₁₀	38.8	52.8	60
PM _{2.5}	64.1	87.5	100
SO ₂	8.9	25.8	80
NO ₂	9.1	33.4	80

- iii. परिक्षेजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता— ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का साम्पन लेवल भारतीय मानक से कम है।
- iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	45.2	69.6	75
Night L _{eq}	38.2	58.6	70

जो जलक लेवल के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- v. पी.सी.यू. की गणना— भारी वाहनों / मल्टीएक्सल डेवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रेफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार—

Status	PCU / Day
Before operation of the expansion project	16,860.5
After operation of the Proposed expansion project	17,397.5

विस्तार के उपरान्त भी री-मटेरियल / प्रोजेक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड बरिंग क्षमता निर्धारित मानक (As per IRC: 73-1980 carrying capacity 20,000 PCU per day for National Highway) के भीतर है।

13. लोक सुनवाई दिनांक 18/04/2022 घात: 10:30 बजे स्थान — सीएसआईटीसी भवन के परिसर, औद्योगिक क्षेत्र, फेस-2, सिलचरा, जिला-रायपुर में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई प्रस्तावोज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 13/08/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

14. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दों/विचार प्रस्तुत किये गये हैं—

- i. सिद्धि बेरोजगारी को योग्यतानुसार रोजगार प्रदान किया जाए। साथ ही रोड डेवलपमेंट, गांव के विकास, नहर, नाली के विकास आदि में भी सहयोग प्रदान किया जाए।

- ii. उद्योग के क्लियर से प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। सड़कों में डस्ट उत्सर्जन अत्यधिक मात्रा में होती है।
- iii. उद्योग की वाहनों के आवागमन से आस-पास के सड़क मार्ग प्रभावित होते हैं, जिससे आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
- iv. उद्योग के अंदर कृषासेपम पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है—

- i. वर्तमान में उद्योग में लगभग 350 से 400 लोग काम कर रहे हैं जिसमें से 7% प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है। स्थानीय ग्राम की साथ-साथ समीपवर्ती ग्रामों में विकास कार्य किया जाएगा।
 - ii. उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण हेतु वेप फिल्टर की स्थापना की गई है जिससे पर्यावरण प्रभावित न हो। सड़कों की सफाई के लिए मशीन लगा हुआ है एवं सीटर टैकर से जल छिड़काव किया जाता है।
 - iii. शौचालय सड़कों का मरम्मत किया जाएगा। साथ ही सड़कों में वाहनों के आवागमनों से होने वाले पर्यावरणीय डस्ट उत्सर्जन को रोकथाम हेतु जल छिड़काव का कार्य किया जाएगा।
 - iv. कृषासेपम हेतु 30 एकड़ में से 11.50 एकड़ भूमि में पीछे खेपित किये गये हैं जिसमें लगभग 14,000 पीछे लगे हुए हैं एवं प्रतिवर्ष अधिक से अधिक कृषासेपम करने की कोशिश करती है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं कृषासेपम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सम्मति विस्तार से वर्षा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Additional Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
2700	1%	27	Following activities at Village-Bhalsmuda	
			Eco-Park Niman	28.28
			Total	28.28

सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 3,500 वर्ग मीटरों के लिए राशि 7,17,500 रुपये, पौंसिंग के लिए राशि 8,00,000 रुपये, छाद एवं सिंचाई के लिए राशि 1,75,000 रुपये, रख-रखाव के लिए राशि 1,64,250 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 18,56,750 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 11,69,250 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत ईको पार्क निर्माण हेतु ग्राम पंचायत बैलसमुदा के सहमति उपरांत पर्यावरणीय स्थान (खसरा क्रमांक 22/3/साई), क्षेत्रफल 2.5 हेक्टेयर) के समक्ष में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत कुल लागत

के 2 प्रतिशत अनुसार प्रस्ताव (बी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही ईको पार्क निर्माण के अतिरिक्त प्रस्तावित स्कूल में किये जाने वाले कार्य का विस्तृत प्रस्ताव (बी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. भूमि स्वामित्व/भूमि आवंटन संबंधी दस्तावेज खसरावार सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. उपलब्ध जैवोद्योगिक दूषित जल अनुसार इपल्युरेंट ट्रीटमेंट प्लांट एवं घरेलू दूषित जल अनुसार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था हेतु जानकारी (समता, ड्राईंग स्कीम) प्रस्तुत किया जाए।
3. स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकाल्य उपर्युक्त उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की समता कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों की उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट की संख्या सहित एवं विगनी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. उद्योग में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
6. उद्योग परिसर के चारों ओर एवं उद्योग क्षेत्र के रिक्त स्थान में भी अर्थात् 50 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पीछों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), बुझा हेतु पेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रथ-रथार को लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव ले-आउट प्लान में दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाए।
7. वर्तमान में स्थापित इकाईयाँ हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन अनुसार शर्त क्रमांक 3 के अनुरूप पालन का पूर्ण पालन करने के संकल्प में कार्ययोजना एवं जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
8. बी.पी.आर. के तहत कुल लागत की 2 प्रतिशत अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ईको पार्क निर्माण के लिए विस्तृत प्रस्ताव (बी.पी.आर.) के अतिरिक्त प्रस्तावित स्कूल में किये जाने वाले कार्य का विस्तृत प्रस्ताव (बी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।
9. उद्योग परिसर के अंदर स्थान वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पीछों का सरवाइवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को समस्त रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परिशोधना प्रस्तावक द्वारा स्थानीयों के समक्ष दिये गये आवेगान को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंशरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंशरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

14. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के फालन में जी नई कार्यवाही की बिन्दुवार शर्तों का पूर्ण फालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त बाधित जानकारी/दस्तावेज प्रदा होने उपरान्त अगामी कार्यवाही की जायेगी।

तदनुसार एच.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 21/03/2023 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/04/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 464वीं बैठक दिनांक 11/05/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. भूमि स्वामित्व/भूमि आवंटन संबंधी दस्तावेज सरासरी सहित प्रस्तुत किया गया है।
2. जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था — औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उपभोग होता है। कुलित उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलित हेतु उपयोग में लाया जाता है। वही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकाल हेतु अपनाई जाएगी। पीपर प्लांट से जनित दूषित जल के उपचार हेतु इम्प्लूमेंट ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं लोकप्रित निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकाल उपरांत घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु एनबीसीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 20 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना किया गया है। वही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकाल हेतु अपनाई जाएगी। गैसीफायर से जनित किनासिक वेस्ट वाटर को डी.आर. आई, किलन के आउटर बरनिंग केम्बर में जलाये जाने का प्रस्ताव है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।
3. प्रदूषण मार संबंधी जानकारी — वर्तमान में स्थापित स्प्रेड अव्ययन किलन से पार्टिकुलेट मैटर 80 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 27 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डीऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 821.04 टन प्रतिवर्ष है। वर्तमान में स्थापित इम्प्लूमेंट फर्नीचर से उत्पादन की दशा में पार्टिकुलेट मैटर 80 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 8.18 टन प्रतिवर्ष है तथा स्थापित एफ.बी.सी. आधारित पीपर प्लांट से पार्टिकुलेट मैटर 80 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 48.6 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डीऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 182.3 टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकार स्थापित इकाई से कुल पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 84.78 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डीऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 783.34 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्तावित कार्यकालाप उपरान्त स्थापित इम्प्लान्तन फर्नेस (2x8 टन) के स्थान पर प्रस्तावित इम्प्लान्तन फर्नेस (2x10 टन) से उत्पादन की दशा में पार्टिकुलेट मैटर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 15,452 टन प्रतिवर्ष होगा जब नवीन इम्प्लान्तन फर्नेस (2x15 टन) से उत्पादन की दशा में पार्टिकुलेट मैटर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 20,738 टन प्रतिवर्ष होगा। प्रस्तावित टी-हीटिंग फर्नेस आधारित सेलिंग मिल से उत्पादन की दशा में पार्टिकुलेट मैटर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 8,221 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डाईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 215.138 टन प्रतिवर्ष होगा। स्थापित स्पंज आयरन किचन एवं स्थापित एच.बी.सी. आधारित पीपर प्लांट से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन एवं सल्फर डाईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। इस प्रकार प्रस्तावित कार्यकालाप उपरान्त कुल पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 123,509 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डाईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 895.478 टन प्रतिवर्ष होगा।

समिति द्वारा पाया गया कि प्रस्तावित क्षेत्र कितारा औद्योगिक क्षेत्रांतर्गत है, जिसके कारण नाननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 10/07/2019 एवं दिनांक 23/08/2019 के अनुक्रम में इलीमिनेट पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा कार्यालय आदेश जारी किया गया है। जिसके अनुसार "In expansion and diversification activity, the pollution load shall not exceed the existing load for which consent has been granted." जारी किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्थापित इकाई से समस्त विस्तार उपरान्त प्रस्तुत प्रदूषण भार की गणना अनुसार बड़ीतरी हो रही है। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तुत प्रदूषण भार की गणना अनुसार विचार किया जाना संभव नहीं है। अतः पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन एवं सल्फर डाईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा में कमी करती हुए पुनः प्रदूषण भार की गणना कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 3 नग 750 के.वी.ए. एक्सिस्टिंग इंफ्लोअर में स्थापित है, जिसमें विन्नी की ऊंचाई बिल्डिंग की ऊंचाई से 3.5 मीटर अधिक है। किया जाना प्रस्तावित है।
5. उद्योग में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में प्रस्तुत प्रस्ताव में कुल क्षेत्रफल कर 40.08 प्रतिशत में कुसारीयता प्रस्तावित किया गया था। वर्तमान में पुनः उद्योग परिसर का परीक्षण उपरान्त कुल क्षेत्रफल के 42.9 प्रतिशत क्षेत्र में कुसारीयता किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जिसके तहत प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछे के लिए राशि 8,19,000 रुपये, सिंचाई तथा खाद के लिए राशि 1,50,000 रुपये, रख-रखाव के लिए राशि 1,64,250 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 9,29,250 रुपये एवं आगामी 4 वर्ष हेतु कुल राशि 18,61,013.23 रुपये घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति शर्त के अपूर्ण पालन (स्थापित इम्प्लान्तन फर्नेस में सी.ई.एम.एस. की स्थापना नहीं करने) का पूर्ण पालन करने के संबंध में बताया गया कि नियमानुसार इम्प्लान्तन फर्नेस में सी.ई.एम.एस. की स्थापना किया जाना अनिवार्य नहीं है। अन्य इकाई जैसे कि स्थापित स्पंज आयरन एवं एच.बी.सी.

आधारित पीयर प्लॉट में सी.ई.एम.एस. की स्थापना की गई है। प्रस्तावित कार्यक्षेत्राव संपत्ति इन्फ्रस्ट्रक्चर कर्नेस एवं वि-डीटिंग कर्नेस रोलिंग मिल में सी.ई. एम.एस. की स्थापना प्रस्तावित है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु ब्राऊन फिल्ड होने के कारण पूर्व में सी.ई.आर. के तहत प्रस्तुत कुल लागत का 1 प्रतिशत प्रस्ताव (28.26 लाख) को कन्य किये जाने का अनुरोध किया गया है। समिति का मत है कि प्रस्तावित परियोजना समिति के समक्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रथम बार आवे जाने के कारण सी.ई.आर. के तहत कुल लागत को 2 प्रतिशत अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही ईको पार्क निर्माण के लिए विस्तृत प्रस्ताव (सी.पी.आर.), के अतिरिक्त प्रस्तावित स्कूल में किये जाने वाले कार्य का विस्तृत प्रस्ताव (सी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. उद्योग परिसर की अंदर सभ्य कृषासंपन्न किये जाने एवं वेपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सभ्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थानीय लोगों को सनसा रोजगार दिये जाने हेतु सभ्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. जमसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा छाबीणी के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु सभ्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सभ्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देह के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सभ्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संजालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रकरण का प्रकरण लंबित नहीं है।
14. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संजालय बेंदल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के चलन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार शर्तों का पूर्ण चलन किये जाने बाबत सभ्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन एवं सल्फर डीऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा में कमी कक्षों हुए नून प्रदूषण मान की गणना कर प्रस्तुत किया जाए।
2. ईको पार्क निर्माण के लिए विस्तृत प्रस्ताव (सी.पी.आर.), के अतिरिक्त प्रस्तावित स्कूल में किये जाने वाले कार्य का विस्तृत प्रस्ताव (सी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त उल्लिखित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

उदानुसार एच.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के डायन दिनांक 04/07/2023 के परिषद में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/07/2023 को जानकारी/प्रस्तावक प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 400वीं बैठक दिनांक 10/08/2023

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. प्रदूषण भार संबंधी विवरण:- परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरंत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की संबंधित गणना कर (प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा) निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत किया गया है:-

- वर्तमान में स्थापित स्पंज आयरन किलन से पार्टिकुलेट मैटर 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 27 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डीऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा 821.04 टन प्रतिवर्ष है। वर्तमान में स्थापित इन्फ्रारुड फर्नेस से उत्पादन की दशा में पार्टिकुलेट मैटर 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 8.18 टन प्रतिवर्ष है तथा स्थापित एक.बी.सी. अस्थापित पीपर प्लांट से पार्टिकुलेट मैटर 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 48.8 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डीऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा 182.3 टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकार स्थापित इकाई से कुल पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 84.78 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डीऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा 783.34 टन प्रतिवर्ष है।
- प्रस्तावित क्लर्कलाय उपरंत स्थापित इन्फ्रारुड फर्नेस (2x8 टन) के स्थान पर प्रस्तावित इन्फ्रारुड फर्नेस (2x10 टन) से उत्पादन की दशा में पार्टिकुलेट मैटर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 15.562 टन प्रतिवर्ष होगा तथा नवीन इन्फ्रारुड फर्नेस (2x15 टन) से उत्पादन की दशा में पार्टिकुलेट मैटर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 20.736 टन प्रतिवर्ष होगा। प्रस्तावित पी-हीटिंग फर्नेस अस्थापित होलिंग मिल से उत्पादन की दशा में पार्टिकुलेट मैटर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 0.6221 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डीऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा 21.8136 टन प्रतिवर्ष होगा। वर्तमान में स्थापित स्पंज आयरन किलन के कम प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की दक्षता (Efficiency) में वृद्धि एवं उच्च गुणवत्ता के कोयले का उपयोग किया जाकर पार्टिकुलेट मैटर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 18.2 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डीऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा 607.5 टन प्रतिवर्ष होगी तथा स्थापित एक.बी.सी. अस्थापित पीपर प्लांट के कम प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों

की क्षमता (Efficiency) में वृद्धि किया जाकर पार्टिकुलेट मेटर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 29.18 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डीऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा 143.82 टन प्रतिवर्ष होगी। इस प्रकार प्रस्तावित कार्यालय उपरोक्त कुल पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 82.27 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डीऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा 172.831 टन प्रतिवर्ष होगी।

2. ईको पार्क निर्माण के लिए विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.), के अतिरिक्त प्रस्तावित स्कूल में किये जाने वाले कार्य का विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्कूल में कार्य प्रस्तावित किये जाने के स्थान पर ग्राम पंचायत मैसकुड़ा से ईको पार्क निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि 2.5 हेक्टेयर हेतु अनुरोध किया गया। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत ईको पार्क निर्माण के लिए संशोधित विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया गया है:-

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
2700	2%	54	Following activities at, Village-Bhalemuda	
			Eco Park Niman	54.79
			Total	54.79

सी.ई.आर. के अंतर्गत 'ईको पार्क निर्माण' हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 8,000 नग फीटों के लिए राशि 18,40,000 रुपये, ड्रेनिंग के लिए राशि 9,00,000 रुपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 4,00,000 रुपये, रथ-रथाव के लिए राशि 2,82,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 32,32,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 22,47,488 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत ईको पार्क निर्माण हेतु ग्राम पंचायत मैसकुड़ा के सहमति उपरोक्त व्यवसाय स्थान (खसरा क्रमांक 22/3(पाटी), क्षेत्रफल 8.885 हेक्टेयर में से 5 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मेसर्स पारापानी इन्फ्रस्ट्रक्चर लिमिटेड, ग्राम-सोम्बड़ा, तहसील व जिला-रायपुर में प्रस्तावित कार्यालय के तहत ग्राम-सोम्बड़ा, तहसील व जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 404, 405/1, 405/2, 406/1, 406/2, 406/3, 406/4, 407/1, 407/2, 409/1, 409/2, 409/3, 410/1, 410/2, 411/1, 411/2, 412, 413, 414, 415, 416/1, 416/4, 416/5, 416/6, 416/7, 417/1, 417/2, 417/3, 417/4, 417/5, 417/6, 418/1, 418/2, 418/3, 418/4, 419, 454/1, 454/2, 458, 459, 463/1, 463/2, 463/3, 463/4, 463/5, 463/6, 463/7, 463/8 एवं

484/1, सीकरकल - 11.88 हेक्टर से 18.8 हेक्टर (48.9 एकड़) में इण्डियन कर्नेस विथ एल.आर.एफ. से (एम.एस. बिलेट, इगाटस/हीट बिलेट्स) - 38,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,50,000 टन प्रतिवर्ष, न्यू सेलिंग मिल (सि-टील्ड प्रोडक्ट/पत्र/स्ट्रक्चरल्स स्टील/वायर रॉड) - 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु परिसिस्ट-38 में वर्णित शर्तों को अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

ईदक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संलग्न हुई।

(अनंदकुमार सिंघी)

सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(बी. सी. नानंद)

अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

नेहरू मोडर्नल महिला स्वच्छाघरा समूह, तैलगुड़ा नौसाबटी, जयपूर-बीमली सगीता पील (तैलगुड़ा सेक्टर माईनिंग-1) को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल क्षेत्रफल-4.9 हेक्टेयर में क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, घास-भुईयांव, घास-तैलगुड़ा, तहसील-बारामा, जिला-उत्तर बरसात कांकर (छ.ग.) में महानदी से रेत उत्खनन क्रमात् 44,100 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु की जायेगी।
2. सस्टेनेबल सेक्टर माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाइन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स फॉर सेक्टर माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स फॉर सेक्टर माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. गांव अध्ययन (मिस्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में लगभग 1.5 वर्ष में विस्तृत गांव अध्ययन (Situation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाधित नहीं हो सके, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आवांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों ओरों तथा सीमा लाइन के नजद में सीमेंट के छप्पे गड़ना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र सही में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, जवहा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार रेत उत्खनन क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन गहराई से 1.5 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 44,100 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।
10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने से पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित पिछ बिन्दुओं पर नदी में रेत की सहाह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ों तालिका एच.ई.आई.ए.

ए. धर्तीसंग्रह को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक लम्बा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन प्रारंभ मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के सांकेही अगस्त 2023, 2024, 2025, 2028, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून के सांकेही अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एन.ई.आर.ए.ए., धर्तीसंग्रह को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भराई कनिष्ठों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। निम्न वेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) में लॉडिंग ग्राइट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेलर द्वारा किया जाएगा।
12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हाई रीक) को ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर ऊंचा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिस, स्टेशन, बॉट, एनीकॉट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थानीय संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, तर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विचलित प्रभाव न पड़े।
15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्मित न हो। कचुओं के प्रजनन इकाईयाँ / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अंधे उत्खनन पाये जाने की स्थिति में परिवेक्षण प्रस्तावक को विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाही की जायेगी।
17. परिवेक्षण प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रजाती वन्य जीवों / अनलॉडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले क्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण,

घन और जल वायु परिवर्तन, मंडलमय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से डके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं करा जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. उत्खनन क्षेत्र में खनिज प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
20. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु तीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, वीरू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,500 मग पौधों का रोपण नदी तट पर रोकित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त कुलरोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आदेश का राज्य पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।
21. रोकित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का चस्केट करते हुये फोटोग्राफस सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
22. कुशारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
23. किये गये कुशारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये उत्तीरगढ़ पर्यावरण संरक्षण समूह एवं एस.ई.आई.ए.ए., उत्तीरगढ़ को प्रेषित किया जाए।
24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
27.36	2%	0.54	Following activities at nearby Village-Teiguda	
			Plantation around Pond & AMC for 5 years	0.50
			Total	0.50

25. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित धान पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। कुशारोपण अक्षरगत होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के धारों और वृक्षारोपण हेतु (आम, जामुन आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 25 नव पीढी के लिए राशि 1,000 रुपये, खेडिंग के लिए राशि 1,500 रुपये, खाद के लिए राशि 500 रुपये, सिंचाई तथा बस-सहाय्य आदि के लिए राशि 15,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 18,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 42,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-तैलगुड़ा, ग्राम पंचायत भिलाई के सहजद्वि उपरंत व्यापारिक स्थान (ग्राम-तैलगुड़ा के खसरा क्रमांक 838 एवं 839 में स्थित तालाब) के संरक्ष में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
27. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रामपंचायत/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरंत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर जाये, तब वहाँ खदान/खडौन/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केंद्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियाँ प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / कार्रवाईका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
31. छत्तीसगढ़ नौग खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्रावधानों/हर्ती एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
32. कार्य स्थल पर यदि कंमिंग भूमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे भूमिकों को आवरण की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। कालस्थाय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाना जा सके।
33. भूमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विकिरणशील सुविधा, मोबाइल टॉपलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद सामग्री के पैकेट, प्लॉस्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जाये।
34. भूमिकों का समय-समय पर आकूपेक्षण हेतु सर्विलेंस कराया जाये।
35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एरा.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिधान मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आदेश किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार रखने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारी के अधिकतम अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की स्मरणा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के उल्लंघन से बचने के पालन न करने की वशा से किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्कास के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आदेश की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में उपलब्ध हैं। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट paawesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की ऊर्ध्व वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदात शर्तों के पालन की निगरानी की जाएगी।
40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों की शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली निगरानी हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपेक्षित (प्रदूषण हत्यालय एवं भीमाघार संघलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
42. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की वशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन ज्ञानकारी सहित सूचित किया जाए ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाधित निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए.,

मेसर्स सिरी सैण्ड क्वारी (सिविड/सराय, ग्राम पंचायत सिरी)

को खदान क्रमांक 21, कुल क्षेत्रफल-3.035 हेक्टेयर में क्षेत्र का कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम-सिरी, तहसील-पसान, जिला-कोरवा (छ.ग.) में बलनी नदी से रेत उत्खनन क्षमता 18,210 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में की जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को अंगीकार दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे को निष्काशन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सैण्ड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सैण्ड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सैण्ड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 80 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. गारड अध्ययन (सिस्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गारड अध्ययन (Station Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःपूरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन कर नदी, नदीतट, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अर्थात् एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनों तथा सीमा लाइन के मध्य में सीमेंट के खम्भे गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माइनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 3.035 हेक्टेयर के कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन साइट से 1 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 18,210 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. मानवीय एन.डी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माइनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक निपुस्त करना होगा।
10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित फिज बिन्दुओं पर नदी में रेत की साइट के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एराई.आई.ए.

ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं विच बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह को रेतों (Layers) का सर्वे पूर्व निर्धारित विच बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं विच बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित विच बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 8 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भरवाई भूमिकाई द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिकर क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लैंडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेलरों द्वारा किया जाएगा।
12. रेत का उत्खनन केवल विन्हील, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोन्नों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हाई रीक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
13. रेत उत्खनन नदी तटी से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटी का क्षरण न हो। किसी भी जूलिया, स्टापरेन, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वल्प पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु जनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इसाईयाँ / सेजों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
16. रेत उत्खनन एवं भरवाई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अंधेरा उत्खनन पाये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के विस्तृत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रकारों तथा लैंडिंग / अनलैंडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले क्यूम्युलिटिव इस्ट कार्बर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त बाधु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण,



वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. पालखन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
20. स्वास्थ्यका के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में नवीलाट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, पीप, करंज, शीशु, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 700 मग पीपों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कस्टोडियर टापर की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 बीट से 6 बीट ऊंचाई वाले पीपों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पीपों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी अन्वय का प्रथम पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पीपों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।
21. रोपित किये जाने वाले पीपों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीपों के नाम का उल्लेख करते हुए फोटोग्राफस सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
22. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पीपों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये उत्तीर्णक पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय एवं एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीर्णक को प्रेषित किया जाए।
24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए--

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
28.968	2%	0.579	Following activities at nearby	
			Pavitra Van	0.579
			Nirman	
			Total	0.579

25. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित काम संकायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना अथवा उत्तरदायित्व होना। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत "परिवर्तित वन निर्माण" के तहत (बसू, नीम, पीपल, बेल, आंवला, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नव पौधों के लिए राशि 5,000 रुपये, पौंसिंग के लिए राशि 20,438 रुपये, साद के लिए राशि 1,500 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 5,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 31,938 रुपये तथा अगामी 4 वर्षों में कुल राशि 28,000 रुपये हेतु परतकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत सिर्सी के सहमति उपर्युक्त स्थायीय स्थान (खसरा क्रमांक 21/1/क, क्षेत्रफल 0.983 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
27. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रामपंचायत/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलोत्सव पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सल्लाहपत्र कराया जाए।
28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवें, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत जायके द्वारा कचरे एवं कचरों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं चाहे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केंद्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेल उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / जलोत्सव पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
31. जलोत्सव गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेल उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुसूचित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
32. कार्य स्थल पर यदि केंपिंग शक्ति कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे शक्ति कार्य के आवास की उपरि व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
33. शक्तियों के लिए खान स्थल पर स्वच्छ पेयजल डिफिलसक्षीय सुविधा, भोवाइन टाइलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद सामग्री के पैकेट प्लास्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावे।
34. शक्तियों का समय-समय पर आवश्यकतानुसार हेल्थ चेकअप कराया जावे।
35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. जलोत्सव / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार रखने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों को अधिकतम अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
37. एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा से परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों को संशोधन/ वन से पालन न करने की दृष्टि से किसी भी शर्त में संशोधन/ निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उल्लंघन / निर्यात की शर्तों की और साक्षात् करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट mahesh.in पर भी किया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, कोरबा, एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की निगरानी की जाएगी।
40. एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली निगरानी हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाए जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकेतमय अपशिष्ट (प्रबंधन इत्यादि एवं सीमापार संयोजन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
42. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दृष्टि से एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः मधीन जागरूकी सहित सूचित किया जाए ताकि एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तों निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा चन्चलन एम.ई.आई.ए.ए.,

मैसर्स पुनरुद्घाटन लाईम स्टोन माईनिंग (जे- बी विकास अग्रवाल)
की पार्ट ऑफ खदान क्रमांक 46, 50, 51, 52 एवं 53/1, कुल लीज क्षेत्र 1.88 हेक्टेयर,
ग्राम-पुनरुद्घाटन, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग में चूना पत्थर (गीम खनिज) उत्खनन -
19,950 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.88 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दीर्घ में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 19,950 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कक्षाकर परको मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (अथवा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की मुख्य प्रवेश द्वार पर चूकना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अथवा एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के अनुसार पृष्ठाकरण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिष्कृत सड़क तक पहुँच मार्गों के संभारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई-दुर्ग, ए.आई.आई.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
6. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित करावे जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं परेशु दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अतः इन प्रक्रिया में अथवा पृष्ठाकरण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। परेशु दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोलरपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपस्थित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन

और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उगाही वी-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह धारा, कनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान प्राधिकारी से अनुमोदित नई खनन क्षेत्रों प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. भू-जल के उपयोग हेतु केंद्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किया जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
11. किसी किनारी / बैंक / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मि.टी.घण्टा / साप्ताहिक घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। इनपर, सजिन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ साथ झाटा का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न पसूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं निश्चित रूप से किया जाए। न्यूज मार्ग, रैम्प, संवहन क्षेत्र, नराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेंट कम खनिज सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संभारण सुनिश्चित किया जाए। विषम ड्रेजिंग बॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
12. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होगी चाहिए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोटी नई 7.5 मीटर की चौड़ी चट्टी में कोई वेस्ट का डंप / बन्धारण नहीं किया जाए तथा इस चट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पावे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकती।
15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान डटाई गई ऊपरी मिट्टी (टीप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न करने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी औद्योगिक क्षेत्रों के स्थिर (स्टेबिलाइज्ड) करने में किया जाए।
16. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुुरुपयोग, विक्रम एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःसंभारण के लिए किया जाए।
17. ओवरसैंडिंग एवं अनुपयोगी/बिना उपयोग खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से विच्छेदित स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावे ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर

विपरीत प्रभाव न डाल सके। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोम 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डिन डम्प का क्लरिंग रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से पुनरोपचार किया जाए।

18. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डिन एवं अन्य अनुपयोगी/बिड़ी अवशेष खनिज (रेस्ट रीक) को खनन के परधारा बने गड्ढों में पुनःनमन (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा बाँधित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रदूषित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेंनिंग वॉल / गार्लेन्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनिज का परिवहन कन्वई वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को अगला से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
66	2%	1.32	Following activities at nearby, Village-Chunkatta	
			Pavitra Van Niman	12.19
			Total	12.19

22. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरान्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। पुनरोपचार असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
23. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (नीम, आम, कंज, कदम, जामुन, अंबला, अमलतास, बड़, पीपल आदि) पुनरोपचार हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 228 नग पौधों के लिए राशि 17,178 रुपये, पौंसिंग के लिए राशि 1,02,800 रुपये, खाद के लिए राशि 1,710 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,28,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,47,888 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,71,712 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत चुनकट्टा द्वारा भी विकास अग्रवाल, कुल लीज क्षेत्रफल 3.08 हेक्टेयर एवं श्री विकास अग्रवाल, कुल लीज क्षेत्रफल 1.86 हेक्टेयर को सी.ई.आर. के अंतर्गत पवित्र वन निर्माण हेतु खसरा क्रमांक 404 को क्षेत्रफल 0.31 हेक्टेयर में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
24. सी.ई.आर. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, गड्ढों के रख-रखाव एवं पुनरोपचार

कार्य के ऑफिशियल एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (जेनरल/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिपोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

25. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/खोज/बट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आवक द्वारा कराये गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आवककी जिम्मेदारी होगी।
26. उत्खनन हेतु निश्चित क्षेत्र (घाटी तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), होल रोड, ओवरबर्डन अन्य आदि में स्थानीय जजाटियों के 8022 नम नुमा का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास जेन्द्रीय वृक्षण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
27. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में कम से कम 200 नम प्रति हेक्टेयर जीज क्षेत्र के अनुसार बड़, चीपल, गीम, करंज, सीसू, जाम, इमली, अर्जुन, सौरभ आदि अन्य स्थानीय जजाटियों के 350 पीधे का रोपण (कुल 1,172 पीधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुस्थित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्या कांटेदार तार के बड़ अथवा डी गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संश्लिषित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 6 फीट से 8 फीट लंबाई वाले पीधे का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति लक्ष्य निरस्त की जा सकती है।
28. रोपित किये जाने वाले पीधे में संख्यांकन (Numbering) एवं पीधे के नाम का सल्लेख करते हुये जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफ सल्लिषित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
29. माईनिंग लीज क्षेत्र को अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पीधे का सरवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पीधे को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आवक द्वारा रोपित पीधे के वृक्षारोपण को सफल बनाना आवककी पूर्व जिम्मेदारी होगी।
30. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी एवं सी.ई.आर. जल संसाधन विभाग को प्रेषित किया जाए।
31. परिपोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिने गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिपोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं किये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
32. परिपोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि वृक्षण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपकरण किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले

शमिकों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्साकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

33. कंट्रोल ब्यारिस्टिंग का कार्य सी.जी.एन.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए पक्कर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाइंग ईन्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेद डिजिटल अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित डिजिटल किया जाए, जिससे डस्ट का परसर्जन नियंत्रण में रहे।
34. उत्खनन प्रक्रिया सू-जल स्तर के ऊपर असंतुलन प्रमाण में ली जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया सू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में लही किया जाए।
35. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण अपनाया जायितक होगा।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नीम खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ नीम खनिज नियम, 2016 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। नईन एक्ट 1982 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
37. कार्य स्थल पर यदि कैंपिंग शमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे शमिकों के आवास एवं सुखा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में ही सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
38. शमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्साकीय सुविधा, मोबाइल टायलेंट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
39. शमिकों का समय-समय पर आवश्यकतानुसार हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
40. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
41. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
42. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की संपरेका में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की वशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्काय के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
43. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parbesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
44. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय,

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

45. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्ताव शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
46. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं जाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
47. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निर्वहन) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निर्वहन) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिशुद्धकृतमय और अन्य अपेक्षित (जैसे एवं सीमापार संकलन) नियम, 2010 तथा लोक सचिवालय विनियम, 1981 (ज्याहा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
48. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाध्य निर्णय ले सके। अतः में कोई भी विस्तार अथवा उन्मथन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
49. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की दृष्टि को उनको क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-स्तर एवं तहसील केन्द्र एवं कलेक्टर / तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
50. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

गैसार्स बुनकट्टा लाईव स्टोन माईन (जे- बी विकास अडवाले)
को खसरा क्रमांक 37(पार्ट), 39(पार्ट), 42(पार्ट), 43(पार्ट), 44(पार्ट), 45(पार्ट), 48(पार्ट),
47(पार्ट), 48(पार्ट), 49(पार्ट), 50(पार्ट) एवं 51(पार्ट) कुल लीज क्षेत्र 3.08 हेक्टेयर,
प्राच-बुनकट्टा, छत्तीसगढ़-पाटन, जिला-दुर्ग में चूना पत्थर (ग्रीन खनिज) उत्खनन -
58,250 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। आत इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 3.08 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज सारस विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 58,250 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के नुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अन्तर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (खस संशोधित) के प्रावधानों को तहत रखा जावे।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की मुख्य जल धार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल, आर्सेनल एवं पेट्रोल सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संभारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्ड (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) जमा किया जाए।
6. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार परदेवार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराया जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं फरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) के उपचार के उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए। अतिसु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। फरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु नौ

बाधकता की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जी भी कटोर ही) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि पदार्थ धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उपजती वी-ग्रेसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह धारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पादन हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वयं प्रतिकारिता से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. मू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय मू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य राज्यों से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
11. किसी किनारी / वेट / धाईट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। अक्षर, स्कीम, ट्रांसफर पाइप्ल (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च चालता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न ज्युजिटिव बस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पर्युव मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भट्टाई एवं अन्य बस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं बस्ट कंटेनमेंट कम सर्प्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संचरण सुनिश्चित किया जाए। विन्ड ड्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
12. बाहरी, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के बाहरी तरफ वॉसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
14. लीज क्षेत्र के बाहरी तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं चाहे जाने पर पर्यावरणीय शोकांति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकती।
15. उत्खनन-प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी क्षेत्रों में स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए।
16. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भण्डारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरुपयोग, विनाश एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनर्भरण के लिए किया जाए।
17. ड्रेजर्सबैंक एवं अनुसंधानी/शिडी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से विन्हील स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को

उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भाष्यारित पर्यावरण आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। जीवरबर्डेन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

18. जहाँ तक संभव हो जीवरबर्डेन एवं अन्य अनुपयोगी/बिड़ी अव्यय खनिज (स्टैट रॉक) को खनन के पश्चात बने कट्टी में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा उचित बैकफिलिंग उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिस्ट स्लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु नईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेंशिंग वॉल / कारलेय्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनिज का परिवहन कन्वई वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं चरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
86	2%	1.32	Following activities at nearby Village-Chunkatta	
			Pavitra Van Niman	12.19
			Total	12.19

22. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 लख में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आयका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
23. सी.ई.आर. के अंतर्गत 'पवित्र वन निर्माण' के तहत (बीग, जाम, कंज, कदम, जानुन, जंवल, जमलतास, बड़, पीपल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 228 नव पौधों के लिए राशि 17,176 रुपये, बीसों के लिए राशि 1,02,800 रुपये, खाद के लिए राशि 1,710 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,28,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,47,686 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,71,712 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत चुनकट्टा द्वारा भी विकास अग्रवाल, कुल स्लीज क्षेत्रफल-3.08 हेक्टेयर एवं भी विकास अग्रवाल, कुल स्लीज क्षेत्रफल-1.88 हेक्टेयर, को सी.ई.आर. के अंतर्गत संयुक्त पवित्र वन निर्माण हेतु खतरा क्रमांक 404 की क्षेत्रफल 0.31 हेक्टेयर में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

24. सी.ई.आर., कॉमन इन्स्ट्रायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्स्ट्रायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण कन्सल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्स्ट्रायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्स्ट्रायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
25. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/घट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपकी द्वारा कस्टोडियन के कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
26. उत्खनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (कारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), डील रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1.113 नमूने वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। उचित पट्टी का विकास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
27. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में कम से कम 200 नमूने प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, गीम, करंज, चीरु, जल, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 650 पीपल का रोपण (कुल 1.763 पीपल) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुनिश्चित रखने की शिर्षे उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जब कांटेदार तार के बाड़ लगवा दी गई का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की वशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट लंबाई वाले पीपल का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
28. रोपित किये जाने वाले पीपल में संख्यांकन (Numbering) एवं पीपल के नाम का उल्लेख करते हुए गियोटैग (Geotag) फोटोग्राफा सहित जानकारी फालग प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
29. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पीपल का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए मृत पीपल को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। साथसे द्वारा रोपित पीपल के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
30. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्थात्वार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण कन्सल एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्स्ट्रायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय

70 DBA) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार ध्वनिक उपचार भी कराया जाए।

33. कंट्रोल स्टाफिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए पावर के छोटे-छोटे टूल्स (स्लैब रीक्स) को चलाने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेद ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
34. उत्खनन प्रक्रिया सू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रमाण में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया सू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
35. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि कनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक कनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज नियम, 2016 के प्राक्कान्ठी, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना को अनुसर किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्राक्कान्ठी का पालन किया जाए।
37. कार्य स्थल पर यदि केंब्रिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवासा एवं सुखा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आयासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
38. श्रमिकों के लिए खाने स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
39. श्रमिकों का समय-समय पर आयुपेशन्स हेल्थ सर्विलेंस करना आवश्यक है।
40. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना को अनुस्यू वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपेक्षित सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
41. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकरण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
42. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की सन्देशों में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्सारण के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
43. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सम्बन्धित, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivash.nic.in पर भी किया जा सकता है।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, मिलाई-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
45. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदाता शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
46. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
47. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये विधायी परिसंकटनमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमाचार संयोजन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बिल अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
48. प्रस्तुत परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की वशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः मॉनिटरिंग जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। अटल में कोई भी विचलन अथवा उल्लंघन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
49. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती की उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-कार्यालय एवं जिला केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
50. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मैसर्स बलुवाखार रोपड सर्वोरी (एचएल/सरपंच, ग्राम पंचायत अमडीहा)

को खदान क्रमांक 1, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर में क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम-बलुवाखार, तहसील-फरसाखार, जिला-जयपुर (र.ग.) में ईब नदी से रेत उत्खनन क्षमता 12,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल रोपड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन्स, 2018 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2018) एवं इन्फोरसमेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर रोपड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. इन्फोरसमेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर रोपड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. गांव अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गांव अध्ययन (Station Study) करावेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंख्या, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अक्षरों एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनों तथा सीमा लाइन के मध्य में सीमेंट के खम्भे गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माइनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 2 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। क्षेत्र 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन गहराई से 1 मीटर गहराई तक ही किया जाए 12,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माइनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित करावे जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधित नियुक्त करना होगा।
10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित डिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की गहराई के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ों तत्काल एल.ई.आई.ए. ए. छातीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट-मनसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत

उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं बिन्दुओं में सर्वेक्षण लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित बिन्दुओं पर किया जाएगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरंत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 8 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के अंकड़े दिनांक 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून के अंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. चलीरागढ़ को प्रस्तुत किए जाएंगे।

11. रेत की खुदाई एवं मराई भण्डारण (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्लॉट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घेरेल क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हाई रीक) को ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी भूतिय, स्टांपिंग, बंध, एनीकट, जल प्रवाह व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तक डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल पसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कण्डुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
16. रेत उत्खनन एवं मराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अवैध उत्खनन कार्य जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक को विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभावों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिबिलिटी इनट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण वातावरण जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता मासत संरक्षक वर्षावर्ष, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन तारपीलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से इके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। छानिज का परिवहन कर रहे वाहनों से अलग से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
20. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार जलुन, जलुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, जाम, इमली, पीरसा आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 400 नग पीधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त बाधस्था (जसा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पीधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पीधों की सुखा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी जज्ञाप का समय पर प्रस्तुत किया जाए। रोपित पीधों की सुखा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।
21. रोपित किये जाने वाले पीधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीधों के नाम का चस्का लगा करके हुये फोटोग्राफस सहित जानकारी अर्थात्वारिक रिपोर्ट के साथ जमा करे। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
22. वृक्षारोपण कर रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पीधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्थात्वारिक रिपोर्ट में समाहित करके हुये फलोग्राफस पर्यावरण संरक्षण मन्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. फलोग्राफस को प्रेषित किया जाए।
24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at Govt. Primary School, Village - Baluwabhar	
			Plantation	5.38
			Total	5.38

25. सी.ई.आर. के लक्ष्य निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्थात्वारिक रिपोर्ट में समाहित करके हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आगला उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
26. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण के तहत (नीम, जाम, महुआ आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 70 नग पीधों के लिए रकम 2,450 रुपये,

पौंसिंग के लिए राशि 35,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 50,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,37,400 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 4,00,500 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण अस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

27. सी.ई.आर. एवं फुलरोपण कार्य को मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ओएसआई/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छातीसंगठ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं फुलरोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/उद्योग/घट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आगामी द्वारा कथार्य नये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराया जायकी जिम्मेदारी होगी।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केंद्र / राज्य शासन के विभागी, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेल उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमोदित प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छातीसंगठ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
31. छातीसंगठ ग्रीन खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेल उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
32. कार्य स्थल पर यदि कोयला भणिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे भणिकों को आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात हटाया जा सके।
33. भणिकों के लिए खनन स्थल पर लकड़ा पैवजल विभिन्नाकीय सुविधा, ग्रीनहाउस टायलेंट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लास्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी पार की स्वच्छता का ध्यान रखा जाये।
34. भणिकों का समय-समय पर स्वास्थ्यपरीक्षण हेतु सार्वजनिक कराया जाये।
35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एल.ई.आई.ए.ए. छातीसंगठ / भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनी / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

37. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की कार्यरत में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से चलाने न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्खनन / निरस्त करने के मामलों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करना कि परियोजना को सख्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट swaish.ac.in पर भी किया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के चलाने हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की निगरानी की जाएगी।
40. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संकथ में की जाने वाली निगरानी हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों पर अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंरक्षण अधिसूचना (प्रवेशन स्थालन एवं सीमापार संवर्धन) नियम, 2008 (ज्या संशोधित) तथा लोक सचिवालय बीमा अधिनियम, 1991 (ज्या संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
42. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। अतः नवीन कोई भी विस्तार अथवा उत्खनन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संरक्षण समूह पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला—व्यापार एवं उद्योग केंद्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR BUILDING PROJECT BY M/S SHIVAY INFRA (PARTNER – SHREE RAJESH KUKREJA) AT LABHANDI, TEHSIL & DISTRICT- RAIPUR IN PROJECT AREA – 1.27 HA FOR THE PROPOSED BUILTUP AREA – 25,999.9 M²

I. Statutory Compliance:

- i. The project proponent shall obtain all necessary clearance / permission from all relevant agencies including Town & Country planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.
- ii. The project proponent shall obtain permission for this project from Chhattisgarh Real Estate Regulatory Authority, Raipur (if required).
- iii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of Buildings due to earthquakes, adequacy of fire fighting equipment etc. as per National Building Code including protection measures from lightning etc.
- iv. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1986 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/ Committee.
- v. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water / surface water required for the project from the competent authority.
- vi. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
- vii. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.
- viii. The provisions of the Solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (as amended) and the Plastic Waste (Management) Rules, 2016 (as amended) shall be followed.
- ix. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power strictly. Use of chillers shall be CFC & HCFC free.

II. Air Quality Monitoring And Preservation

- i. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi notification GSR 94/E dated 25/01/2018 of regarding mandatory implementation of dust mitigation measures for Construction and Demolition Activities for projects requiring Environmental Clearance shall be complied.
- ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.
- iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released (e.g. PM₁₀ and PM_{2.5}) covering upwind and downwind directions during the construction period.
- iv. Diesel power generating sets proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.
- v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures (for eg. Dust sprinkling, covering with green net etc.) shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust wind breaking walls all around the site (at least 3 meter height). Plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, mumm and other construction materials prone to causing dust pollution at the site as well as taking out debris from the site.
- vi. Sand, mumm, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.
- vii. Unpaved surfaces and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.
- viii. All construction and demolition debris shall be stored at the site (and not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.

- h. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.
- i. The gaseous emissions from DG set shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.
- ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

81. Water Quality Monitoring And Preservation

- i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape, and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rainwater.
- ii. Design of Buildings shall follow the natural topography as much as possible. Minimum cutting and filling should be done.
- iii. Total fresh water requirement at the time of construction phase capacity 140.58 m³/day shall not exceed in the existing and the proposed project.
- iv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur along with six monthly Monitoring reports.
- v. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed, the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.
- vi. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be pervious. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as pervious surface.
- vii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water for flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.
- viii. Use of water saving devices/ fixtures (viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.
- ix. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.
- x. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.
- xi. The local bye-law provisions on rain water harvesting should be followed. If local bye-law provision is not available, adequate provision for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building Byelaws, 2015. Rain water harvesting recharge stor/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.
- xii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bore of minimum one recharge bore per 5,000 square meters of built up area and storage capacity of minimum one day of total fresh water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority. Project proponent shall develop rainwater-harvesting structures for 100% harvesting of rainwater in the premises for recharging the ground water table. Rainwater from open spaces shall be collected and reuse for landscaping and other purposes. Rooftop rainwater harvesting shall be adopted for the buildings & residential blocks to be constructed by individual owners. Every building shall have rainwater-harvesting facilities. The storm water flowing in roadside drains shall also be recycled and reused to maintain the vegetation and discharged into natural water bodies. Before recharging the surface runoff, pre treatment must be done to remove suspended matter and oil & grease. Rainwater harvesting pits shall be constructed as per proposal.
- xiii. The project proponent shall complete construction of rainwater harvesting structure within four months.
- xiv. All recharge should be limited to shallow aquifer.
- xv. Water shall be sourced from Raipur Municipal Corporation. No ground water shall be used during construction phase of the project before prior permission from CGWA.

- xvi. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.
- xvii. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur along with six monthly Monitoring reports.
- xviii. Sewage shall be treated in the STP (bar screen, oil grease trap, equalization tank, MBR tank, sand filter, activated carbon filter, filter press and sludge drying bed) with tertiary treatment. The treated effluent from STP shall be recycled/used for flushing, AC make up water and gardening after disinfection. As proposed, no untreated water shall be disposed into municipal drain. As far as possible, zero discharge condition shall be maintained. Project proponent shall construct pucca drain upto nearest municipal drain. Project proponent shall install separate electric metering arrangement with line totalizer for the running of pollution control systems. The record (logbook) of power & chemical consumption for running the pollution control systems shall be maintained.
- xix. The capacity of Sewage Treatment Plant Capacity shall not be less than 125 m³/day.
- xx. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.
- xxi. Onsite sewage treatment of capacity of treating 100% waste water to be installed. The installation of the Sewage Treatment Plant (STP) shall be certified by an independent expert and a report in this regard shall be submitted to the Ministry before the project is commissioned for operation. Treated waste water shall be reused on site for landscape, flushing, cooling tower, and other end-uses. Excess treated water shall be discharged as per statutory norms notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Natural treatment systems shall be promoted.
- xxii. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problem from STP.
- xxiii. Sludge from the onsite sewage treatment, including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Central Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013. The sludge generated from Sewage Treatment Plant (after drying) shall be used as manure for gardening purpose.

IV. Noise Monitoring And Prevention

- i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/ambience zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitored during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB / SPCB.
- ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as a part of six-monthly compliance report.
- iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground-run boys, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation Measures

- i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured. Buildings in the States which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.
- ii. Outdoor and common area lighting shall be LED.
- iii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.
- iv. Energy conservation measures like installation of LED for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.
- v. Solar, wind or other Renewable Energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level / local building bye-laws requirement, whichever is higher.

- v. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.

VI. Waste Management

- i. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the M.S.W. generated from project shall be obtained.
- ii. Disposal of mud during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.
- iii. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste shall be segregated into wet garbage and inert materials.
- iv. Organic waste compost/ Vermiculture pit/ Organic Waste Converter within the premises with a minimum capacity of 0.3 kg /person/day must be installed.
- v. All non-biodegradable waste shall be handed over to authorized recyclers for which a written tie up must be done with the authorized recyclers.
- vi. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.
- vii. Use of fly ash based bricks / blocks / tiles / products shall be ensured. Blended cement with fly ash shall be used. The provisions of notification issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India regarding use of fly ash must be complied with. Appropriate usage of other industrial wastes shall also be explored. Soil borrow area should be filled up with ash with proper compaction and covered with topsoil kept separately. Fly ash / pond ash shall be used for low-lying areas filling, in embankments / road construction etc. ash shall be utilized as per guidelines of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India / Central Pollution Control Board / Indian Road Congress etc. concerning authorities. The use of perforated brick / hollow blocks / fly ash based lightweight aerated concrete etc. shall also be ensured so as to reduce load on natural resources.
- viii. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provision of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003, 25th January, 2010 and 31st December 2001. Ready mixed concrete must be used in building construction.
- ix. Any wastes from construction and demolition activities related thereto shall be managed so as to strictly conform to the Construction and Demolition Rules, 2016.
- x. Used CFLs, LEDs and TFLs should be properly collected and disposed off / sent for recycling as per the prevailing guidelines / rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

VII. Green Cover

- i. No tree can be felled/transparent unless exigencies demand. Where absolutely necessary, tree felling shall be with prior permission from the concerned regulatory authority. Old trees should be retained based on girth and age regulations as may be prescribed by the Forest Department. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted).
- ii. Green belt shall be developed in an area equal to 33 % of the net planning area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. The greenbelt shall inter alia cover the entire periphery of the constructed. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.
- iii. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.
- iv. Topsoil should be stripped to a depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stockpiled appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetation on site.

VIII. Transport

- i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public, and private networks. Road should be designed with due consideration for environment, and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria:
 - a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic.
 - b. Traffic calming measures.
 - c. Proper design of entry and exit points.
 - d. Parking norms as per local regulation.
- ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.
- iii. A detailed traffic management and traffic decongestion plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the roads within a 05 kms radius of the project is maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of all development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in the 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management plan shall be duly validated and certified by the State Urban Development department and the P.W.D./ competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.
- iv. The project proponent shall use covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of construction materials and C&D wastes.

IX. Human Health Issues

- i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.
- ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, canteen etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
- iv. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. Corporate Environment Responsibility

- i. The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi OM vide F.No. 23-65/2017-IA.II dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. Project proponent shall make CER fund as follows:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
5200	2%	104	Following activities at Village- Amethi	
			Pavitra Van Nirman	111.455
			Total	111.455

Development of "Pavitra-van Nirman" at gram panchayat in Village-Amethi, kharsa no. 442, area 5.4 Ha. as dense and religious plantation. Estimate cost of this plantation is around Rs. 1,11,45,500/-.

- i. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.
- ii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- iii. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Raipur Atal Nagar / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.
- iv. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.
- v. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

XI. Additional Conditions

- i. Local persons shall be given employment during development and operation of the site.
- ii. No additional land shall be acquired for this project.
- iii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.
- iv. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
- v. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.
- vi. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely, PM_{10} , SO_2 , NO_2 (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectional parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.
- vii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.
- viii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.
- ix. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.
- x. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.
- xi. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.
- xii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- xiii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

- vi. SEIAA, Chhattingarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.
- vii. The Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.
- viii. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.
- ix. Any appeal against the EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 15 of the National Green Tribunal Act, 2010.
- x. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA, Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC

Chairman, SEAC

वेस्ट बुरुगांव सेक्टर माईनिंग (जी- सरपंच, ग्राम पंचायत बाबलवाही (श्री एमेश कुमार नेतान)) को पार्ट जीए क्षेत्र क्रमांक 847, कुल क्षेत्रफल-5 हेक्टेयर में क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम-भुरुगांव, ग्राम पंचायत बाबलवाही, तहसील-कारण, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) में महानदी से रेत उत्खनन बनता 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा सफाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्कारण की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेक्टर माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाइन्स, 2018 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2018) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स फॉर सेक्टर माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स फॉर सेक्टर माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. ग्राह अभ्यवन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में लगभग 1.5 वर्ष में विस्तृत ग्राह अभ्यवन (Situation Study) करावेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत सही आकड़े, रेत उत्खनन कर नदी, नदीतट, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीव क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (जीव धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. जीव क्षेत्र के चारों कोनों तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट की खम्भे मड़ाना आवश्यक है ताकि जीव क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी ब्लास्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। क्षेत्र 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1.5 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. मानवीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पट्टेदार ग्राह माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोधक नियुक्त करना होगा।
10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित सिड किन्चुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ों तत्काल एस.ई.आई.ए.

ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किया जाये। पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं विद्युत् बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विद्युत् बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरोक्त मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं विद्युत् बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित विद्युत् बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 8 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एच.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भराई मजदूरों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लॉडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेलरों द्वारा किया जाएगा।
12. रेत का उत्खनन केवल विन्तीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तट (लाई बैंक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टाभलेन, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल लरी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयाँ / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अंधेरे उत्खनन पादे जाने की स्थिति में परिवेजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाही की जायेगी।
17. परिवेजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रजातों तथा लॉडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फेडुमिंटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव कक्ष या अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण,

वन और जल कायु परिलीन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन तारमोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से इसे दूर वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं करा जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
20. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, खीरसा आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,500 नम पीछों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जिसका कर्तव्यदाता को बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पीछों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पीछों की सुखा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पीछों की सुखा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।
21. रोपित किये जाने वाले पीछों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ सहित जागकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट को साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकती।
22. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुये नूत पीछों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
48.5	2%	0.97	Following activities at Nearby Village- Bhuigaon	
			Plantation at government land near by lease area	11.50
			Total	11.50

25. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सम्पत्ता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
26. सी.ई.आर. के अंतर्गत तीन क्षेत्र के समीप हासखीय भूमि में (बड़, पीपल, नीम, करंज, आम, इमली, अर्जुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 2,100 नग पौधों के लिए राशि 1,05,000 रुपये, कीसिंग के लिए राशि 3,15,000 रुपये, बाघ के लिए राशि 21,000 रुपये, राख-रखाव आदि के लिए राशि 1,54,500 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 8,95,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में राख-रखाव हेतु कुल राशि 6,55,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बसनावाही के सहमति उपरोक्त व्यायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 002, क्षेत्रफल 6.78 हेक्टेयर में से 1.80 हेक्टेयर) की संशय में प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
27. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के कोऑर्डिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रामपंचायत/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
28. जल की निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं जाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित कोष / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रैल उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतिवा प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर कोष/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / जलसीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
31. जलसीसगढ़ नौम अग्नि नियंत्रण, 2013, राज्य शासन द्वारा रैल उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
32. कार्य स्थल पर यदि कौनिस अधिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे स्थलों के अवाप्त की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। अवाप्तिय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में ही सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
33. स्थलों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विहितसकीय सुविधा, मोबाइल टायलेंट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में बाल मूत्र विसर्जन, कचरा कूड़ा सामग्री के पैकेट, प्लास्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावे।

[Handwritten Signature]

34. श्रमिकों का समय-समय पर आवेष्टकानाल हेल्थ सर्विसेस कराया जाये।
35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना को अनुसूच्य वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
37. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की सुरक्षा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से चलाने करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा जानाजान / निरस्त के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति होने की 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सफल पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्रवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर की प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में बदला शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। वे शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिशिष्टकृत अपशिष्ट (प्रबंधन इत्यादि एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (तथा

संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.एए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.एए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए ताकि एस.ई.आई.एए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की समझौता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने काया निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.एए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केंद्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करना।
44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की भांति 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

**ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR EXPANSION IN EXISTING
INDUCTION FURNACE WITH LRF (M.S. BILLETS, INGOTS/HOT BILLETS) OF
CAPACITY- 35,000 TONNES / YEAR TO 1,50,000 TONNES/ YEAR, NEW
ROLLING MILL (RE-ROLLED PRODUCT/PATRA/STRUCTURAL STEELS/ WIRE
ROAD) OF CAPACITY- 1,50,000 TONNES / YEAR OF
M/S YASWANI INDUSTRIES LIMITED**

I. Statutory Compliance:

- i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattagam Environment Conservation Board (CECB).
- ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.
- iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

- i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules, 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time, and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through lab recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.
- iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with Fume Extraction System with Bag filters (PTFE) of adequate capacity and high efficiency shall be installed in induction furnace(s) with minimum 30 meter stack height. Collecting hoods with Fume Extraction System with Bag filters (PTFE) of adequate capacity and high efficiency shall be installed in reheating furnace coal gasifier based rolling mill with minimum stack height 47 meter to ensure that particulate matter emission less than 30 mg/Nm³ all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. Project proponent shall install dust extraction system with bag filters in coal handling plants and coal transfer points. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. Proper ventilation shall also be provided in induction furnace plant. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit :-

Particulate Matter	30 mg/Nm ³ (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)
--------------------	--

Project proponent shall provide proper spare provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

- v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattagadh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.
- vi. Sufficient number of mobile or stationary vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.
- vii. Recycle and reuse iron ore fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process.
- viii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.
- ix. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.
- x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit camera (CCTV) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.
- xi. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron etc.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

- i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of effluent (neutralization system) generated from process. The ETP shall have acid proof lining to avoid any chance of under ground water contamination. Sludge generated from effluent treatment plant shall be transferred to sludge drying beds and disposed off as per the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time. Sewage Treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(2) dated 31st March 2012 as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.
- ii. Industry shall ensure that phenolic wastewater shall be procured only in rubber lined tankers/HOPE drums in accordance with the provisions stipulated in Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.
- iii. Phenolic waste water generated from the coal gasifier shall be incinerated in After Burning Chamber of DRG kiln.
- iv. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.
- v. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Raipur Abad Nagar, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattagadh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.
- vi. Gargand drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.
- vii. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.
- viii. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.
- ix. The project proponent shall used the maximum surface water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

- i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as a part of six-monthly compliance report.
- ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

- i. Ensure installation of regenerative type burners on all reheating furnace(s). The project proponent shall not utilize any solid fuel such as coal as fuel directly in the re-heating furnace(s). Only gas from producer gas plant shall be used in reheating furnace(s) rolling mill. Industry shall produce re-rolled products through reheating furnace maximum of capacity 22,000 Tonnes per annum.
- ii. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
- iii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

- i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Furnace slag shall be used as sub base material in road construction will be given to brick manufacturer. End cutting shall be used as raw material in own induction Furnace(s) for steel making. Mill Scales shall be given to nearby ferro alloys manufacturing unit or casting unit. Tar and Oily sludge shall be sold to authorized recyclers / re-processors for proper disposal through incineration. Cinder shall be given to cement plant.
- ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.
- iii. Zinc dross, Zinc ash generated from the galvanizing plant, waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed off as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.
- iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.
- v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.
- vi. The project proponent shall install filter press for dry disposal of sludge received from ETP and shall used the waste as manure in plantation.

VII. Green Belt

- i. Green belt shall be developed in an area not less than 42.50% of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that plantation will be done within 1 year.
- ii. The project proponent shall prepare a GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Public Hearing & Human health issues

- i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- ii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
- iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile ETP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

- i. The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi, OM vide F.No. 22-65/2017-SAJI dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
3700	2%	54	Following activities at Village-Bhalsmuda	
			Eco Park Nirman	54.79
			Total	54.79

- iii. Development of "Eco Park Nirman" at village Bhalsmuda, (thana no. 22/3(part) area 5 hectare) as dense and religious plantation. Estimate cost of this plantation is around Rs. 54.79 Lakhs.
- iv. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned Gram Panchayat of the respective.
- v. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SELAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.
- vi. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- vii. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur / SELAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.
- viii. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.
- ix. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.
- x. Environment Clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2009 (As Amended).

X. Additional Conditions

- i. This EC shall be granted subject to the conditions that the emission level shall not exceed the prescribed limit notified by Central Pollution Control Board failing which this EC shall deemed to be cancelled.
- ii. No additional land shall be acquired for this project.
- iii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.
- iv. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.
- v. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
- vi. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.
- vii. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM₁₀, SO₂, NO₂ (ambient levels as well as stack emissions) or other sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

- vii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.
- ix. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.
- x. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.
- xi. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.
- xii. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.
- xiii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and strict action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- xiv. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.
- xv. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.
- xvi. The Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.
- xvii. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.
- xviii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 10 of the National Green Tribunal Act, 2010.
- xix. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).


Member Secretary, SEAC


Chairman, SEAC